



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

No. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2005/ज्येष्ठ 13, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2005/JYAISTHA 13, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2005

मध्यावधि समीक्षा

अन्तिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और हांगकांग के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पोटैशियम परमैंगनेट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

सं. 15/2/2004-डीजीएडी. — चूंकि, 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और चीनी ताइपेई (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पोटैशियम परमैंगनेट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 30 दिसंबर, 2000 की अधिसूचना सं० 46/1/2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 12.03.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 29/2001-सीमाशुल्क द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8 सितंबर, 2001 को अंतिम जांच परिणाम निकाला और सीमाशुल्क विभाग की दिनांक 01.11.2003 की अधिसूचना सं० 113/2001 जो कि दिनांक 27.05.2005 की अधिसूचना सं० 85/2003-सीमाशुल्क द्वारा संशोधित की गयी थी, द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और चूँकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए चीन जनवादी गणराज्य के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों अर्थात् यूनान प्रोविन्स जियांगसुई काउंटी केमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री, चीन जनवादी गणराज्य ग्रुप स्टार्स केमिकल एल एल सी, यू एस और बीजिंग झांगहुई यूनटोंग इनवेस्टमेंट कंसलटेशन सेंटर, बीजिंग के बीच संयुक्त उद्यम मै0 ग्रुपस्टार्स केमिकल (यूनान) चीन एल एल सी, चीन जन.गण. से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त आवेदक द्वारा प्रदत्त सकारात्मक सूचना के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि निर्यातक द्वारा प्राधिकारी की जानकारी में लायी गयी परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त होगा। प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत से संबंधित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 10.03.2004 को प्रकाशित हुई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लागू रखना चाहिए और क्या शुल्क को समाप्त करने अथवा उसे परिवर्तित करने के बाद क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने अथवा दोनों की संभावना रहेगी।

#### क. मामले की पृष्ठभूमि

3. भारत में घरेलू उत्पादक मै0 यूनिवर्सल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0, मुम्बई द्वारा अक्टूबर, 2000 में दाखिल आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त देशों से आयात के पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के आधार पर अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 8 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 46/1/2000 डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित किए थे। प्राधिकारी द्वारा निकाले गए जांच परिणामों पर कार्यवाई करते हुए केन्द्र सरकार ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर दिनांक 01.11.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 113/2001 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था। तथापि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणामों और केन्द्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ सीगेट (अब सेस्टेट के रूप में पुनर्निर्मित) के समक्ष अपील की थी, याचिका का निपटान करते हुए माननीय सेस्टेट ने मै0 यूनान प्रोविन्स जियांगसुई काउंटी केमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री (वाई पी जे सी सी आई एफ), चीन जनवादी गणराज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन अस्वीकृत कर दिया, जो कि जांच में शामिल थे और उन्हें असहयोगी घोषित

कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इस निर्यातक को प्रदत्त व्याक्तिगत व्यवहार वापस ले लिया गया था और इस कंपनी से हुए निर्यातों पर अवशिष्ट शुल्क लगाया गया था। सेस्टेट के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.05.2003 की अधिसूचना सं० 85/2003-सीमाशुल्क द्वारा शुल्कों में संशोधन कर दिया था। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों में से एक द्वारा दाखिल एक आवेदन के आधार पर शुल्क के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु वर्तमान जांच शुरू की गयी है।

## ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

- (i) समीक्षा की शुरुआत करने के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों और भारत के घरेलू उद्योग को जांच आरंभ अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजीं।
- (ii) नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- (iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।
- (iv) यह जांच 01.01.2003 से 31.12.2003 (जांच अवधि) की अवधि के लिए की गयी थी। तथापि, क्षति की जांच 2000-01 से 2002-03 एवं जांच अवधि के लिए की गयी थी।
- (v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) से अनुरोध किया गया कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच-अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रदान करें।
- (vi) समीक्षा हेतु मूल आवेदक के अलावा चीन के एक और निर्यातक अर्थात् मै० चोंगक्विंग जियालिंग कैमिकल्स लि०, चीन जनवादी गणराज्य से जांच का उत्तर प्राप्त हुआ था जिसने अपना उत्तर भारत में अपने प्रतिनिधियों/आयातक के माध्यम से दिया था।

- (vii) उपर्युक्त अन्य देशों के किसी अन्य निर्यातक ने जांच संबंधी अधिसूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि चीनी ताइपेई एवं हांगकांग की सरकारों ने अपना उत्तर इस तर्क के साथ दिया है कि ये देश, भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं करते हैं ।
- (viii) संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक मै0 यूनिवर्सल केमिकल्स, मुम्बई और मूल जांच में मूल याचिकाकर्ता ने इस समीक्षा का विरोध करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है ।
- (ix) संबद्ध वस्तु के आयातक मै0 कन्हैया लाल एंड कं0 ने भी जांच संबंधी अधिसूचना का उत्तर दाखिल किया है ।
- x) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच से संबंधित विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त सभी विचारों और अनुरोधों पर संभव सीमा तक विचार किया है ।
- xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।
- xii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभव सीमा तक सत्यापन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा । ।
- (xiii) प्राधिकारी ने नियमानुसार सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु सहयोगी निर्यातकों और संबद्ध समीक्षा के लिए आवेदक के आंकड़ों का सत्यापन किया ।
- (xiv) प्राधिकारी ने 30.7.2004 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए किया जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, चीन के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों और ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के आर्थिक प्रभाग ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में शामिल पक्षों से, मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था ।



(xv) इस जांच परिणाम में प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर विचार किया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों और निर्धारण के आधार पर खुलासा ज्ञात विवरण पत्रों के रूप में हितबद्ध पक्षों के समक्ष सामान्य प्रकटन विवरण पत्रों और शामिल पक्षों के समक्ष गोपनीय प्रकटन विवरणों के रूप में दिनांक के पत्र द्वारा किया गया था। हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटन विवरणों की टिप्पणियों पर भी विभिन्न पक्षों द्वारा साक्ष्यों और आंकड़ों पर आधारित तर्कों एवं दावों के संदर्भ में इन परिणामों में विचार किया गया है।

(xvi) 21 दिसंबर को जारी प्रथम प्रकटन के बाद प्राधिकारी ने सामने दिए गए अतिरिक्त तथ्यों तथा तर्कों समेत दिनांक 13 मई, 2005 को प्राधिकारी ने दूसरा प्रकटन भी जारी किया। हितबद्ध पार्टियों के लिए 24 मई, 2005 तक दूसरे प्रकटन के उत्तर में विचार प्रस्तुत करना अपेक्षित था। प्राधिकारी ने जहां तक संगत है, इन निष्कर्षों में इन हितबद्ध पार्टियों के विचारों को विधिवत रूप से शामिल किया है।

(xvii) \*\*\*\* यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है।

#### न. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

5. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद और प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क वाला उत्पाद पोटैशियम परमैंगनेट है जो एक अकार्बनिक रसायन है। पोटैशियम परमैंगनेट एक गहरी बैंगनी रंग की रवादार सामग्री है। यह मैंगनीज, पोटैशियम और आक्सीजन का मिश्रण होता है। उत्पाद गंधहीन और जल में घुलशील है। पोटैशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र के एम एन ओ 4 है। उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2841.61 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा जांच होने के कारण इस जांच में केवल मूल जांच में शामिल उत्पाद ही अंतर्ग्रस्त हैं। किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया गया है इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा संबद्ध देशों से विनिर्मित एवं निर्यातित उत्पाद हर प्रकार से समान हैं।

#### घ. समीक्षा का शुरुआत और दिए गए तर्क

घ.1 समीक्षा हेतु आवेदक अर्थात् मै0 ग्रुप स्टार्स एल एल सी चीन के विचार

6. समीक्षा हेतु आवेदन मै0 ग्रुपस्टार्स एल एल सी चीन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समीक्षा की मांग करते हुए अपने मूल आवेदन में आवेदनकर्ता निर्यातक ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- कि मूल जांच में 1.11.2001 की अधिसूचना संख्या 113/2001 के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया था और मै0 यूनान प्रोविन्स जांगसुई काउंटी केमिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री (वाई पी जे सी सी आई एफ) द्वारा किए गए निर्यातों पर उक्त शुल्क 64 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन की दर से लगाया गया था तथा चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए अवशिष्ट शुल्क 440 अम.डालर प्रति मी0 टन की दर से लगाया गया था । तथापि, घरेलू उद्योग अर्थात् मै0 यूनिवर्सल केमिकल एंड इंडस्ट्री लि0, मुंबई द्वारा दायर एक अपील के आधार पर सेस्टेट ने 20.10.2002 के आदेश द्वारा निर्यातक को असहयोगी निर्यातक माना था और इस पर अन्य निर्यातकों के समतुल्य 440 अमरीकी डालर प्रति मी.टन का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।
- कि इसी बीच निर्यातक अर्थात् वाई पी जे सी सी आई एफ की स्थिति बदल गयी और वाई पी जे सी सी आई एफ की पोटैशियम परमैगनेट यूनिट वाई पी जे सी सी आई एफ द्वारा एक अमरीकी कंपनी अर्थात् मै0 ग्रुप स्टार्स केमिकल एल एल सी, यू एस ए जो अधिकांश शेयरधारक है, के साथ गठित सेनो-अमरीकी संयुक्त उद्योग और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में मै0 बीजिंग झांग्वी यूआन टॉग इन्वेस्टमेंट कंसलटेशन सेंटर , बीजिंग के हाथ में चली गयी । नया संयुक्त उद्यम, मै0 ग्रुप स्टार्स केमिकल्स (यूनान) एल एल सी का गठन पोटैशियम परमैगनेट का विनिर्माण और विपणन करने वाली तथा भारत सहित विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाली एक पूर्णतः निजी शेयर धारक कंपनी के रूप में 23 अप्रैल, 2001 को किया गया था;
- कि चीन के निर्यातों पर निषिद्ध शुल्क 3 से अधिक वर्षों से विद्यमान है और ऐसी उच्च निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद परिस्थितियों और बाजारी स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है जिसके कारण समीक्षा अपेक्षित है;
- कि मूल मामले में निर्यातक अर्थात् मै0 वाई जी जे सी सी आई एफ को उनके आंकड़ों के सत्यापन के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सहयोगी माना था । तथापि, माननीय सेस्टेट का यह मत था कि कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना कैलेंडर वर्ष अर्थात् 1.1.1999 से 31.12.1999 तक के लिए थी जबकि जांच अवधि 1.4.1999 से 31.3.2000 तक की थी और प्रश्नावली में दी गयी सूचना अपर्याप्त और अविश्वसनीय थी तथा सत्यापन भी सार्थक नहीं था क्योंकि लेखा बहियां और अन्य कार्यलयी कागजात चीनी भाषा में थे;
- कि सिनो-अमरीकी संयुक्त उद्यम के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने उचित रिकार्ड रख-रखाव प्रणाली लागू की है और रिकार्ड चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखे जाते हैं जिससे कोई सत्यापन अथवा परीक्षण सरल और अर्थपूर्ण बनाये जा सकेंगे ;
- कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोटैशियम परमैगनेट की कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है और चीन से निर्यात की कीमत से कम कीमत पर चीन से इतर देशों से भारत में भारी आयात हुए हैं ;

- कि भारत में घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत चीन से निर्यातों के उतराई मूल्य से काफी अधिक हैं। चीनी निर्यातों पर निषेधात्मक पाटनरोधी शुल्क से भारतीय बाजार को चीन के निर्यातों के लिए कृत्रिम रूप से अवरुद्ध करके गंभीर विसंगति पैदा कर दी है;
  - कि भारत से ई यू को होने वाले पोटैशियम परमैंगनेट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण अंतर्राष्ट्रीय गतिशील बाजार में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण भारतीय निर्यातों के लिए यूरोपीय बाजार खुले हैं और इसलिए घरेलू उद्योग के उत्पादन के किसी भाग को यदि ई यू बाजार में भेजा जाता है तो देश में मांग एवं आपूर्ति अंतराल की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी।
  - कि हस्तक्षेप अवधि के दौरान सीमाशुल्क में 18.5 प्रतिशत की पर्याप्त कमी रही है जो अपने आप में मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है।
7. घरेलू उद्योग ने जांच प्रक्रिया के दौरान अपने अनुरोधों में समीक्षा शुरू करने के खिलाफ विभिन्न तर्क उठाए हैं। इन तर्कों के उत्तर में आवेदकों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि:
- कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में ऐसा कुछ नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच शुरू करने से पूर्व इस तथ्य का सत्यापन करने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मध्यावधि समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता के संबंध में पर्याप्त सूचना अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में भारतीय नियम करार के तहत दायित्वों से अधिक उदार हैं और इसलिए आवेदक के अनुरोध पर समीक्षा की शुरुआत करना त्रुटिपूर्ण नहीं है। इस संबंध में उन्होंने यह तर्क करने के लिए कि भारतीय नियमों की व्याख्या भारतीय कानूनों के अनुसार किए जाने और न कि डब्ल्यू टी ओ करार के प्रावधानों के अनुसार, मै0 सीमालिन केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में (2003(155) ई एल टी 51-डी ई एल टी आर) सेस्टेट के निर्णय का हवाला दिया है। यह भी तर्क किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में उन परिस्थितियों का भी प्रतिपादन किया जिनके अंतर्गत नगरीय कानून की व्याख्या की जानी है;
  - कि उपर्युक्त विधिक स्थिति के पूर्वाग्रह के बिना ग्रुप स्टार्स ने अपनी याचिका में मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त आधार दिए हैं जब कि कोई साक्ष्य अथवा सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि ऊपर कहा गया है;
  - उन्होंने आगे समीक्षा के आधारों को दोहराया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों का खण्डन किया है कि प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत उनके किसी अनुरोध में कोई भ्रामक सूचना सही है।

## घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में समीक्षा शुरू करने का विरोध किया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है:-

- कि वर्तमान समीक्षा पर्याप्त औचित्य के बिना और आवेदक द्वारा प्रस्तुत भ्रामक अभ्यावेदन के आधार पर शुरू की गयी थी ।
- कि चीन के एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक (इस मामले में याचिकाकर्ता और इन अनुरोधों में याचिकाकर्ता कहा गया है) ने पूर्ववर्ती जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पर्याप्त सहयोग नहीं किया । चीनी भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत करने के अलावा निर्यातक ने लगभग नगण्य सूचना प्रदान की थी जिसके आधार पर माननीय सेस्टेट ने यह टिप्पणी की कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातक द्वारा किए गए प्रस्तुत अनुरोधों को अस्वीकार कर देना चाहिए था ।
- कि निर्यातक अतीत में न केवल भारत में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष झूठे और भ्रामक दावे करते हुए पाया गया है बल्कि अमरीकी वाणिज्य विभाग के समक्ष भी उसी उत्पाद के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में, जिसके लिए अमरीकी वाणिज्य विभाग ने ग्रुप स्टार सहित चीन जनवादी गणराज्य (पी आर सी) को 128.94 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया जो कि उस कार्यवाही में किसी पक्ष के लिए परिकलित सर्वोच्च मार्जिन है ।
- कि निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों को पूरा करने के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य की ही पुष्टि करने के लिए उसने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं ।
- कि इस बात का अनुमान लगाते हुए किन्तु उसे स्वीकार न करते हुए कि निर्यातक ने अपने पाटन माजिन की समीक्षा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया था, उसमें शामिल सभी देशों के खिलाफ समूचे मामले की समीक्षा औचित्यपूर्ण नहीं बनती है चूँकि समीक्षा का अनुरोध चीन के एक निर्यातक ने किया था इसलिए उक्त समीक्षा केवल चीन से हुए आयातों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए थी । घरेलू उद्योग ने नियम 23 और पाटनरोधी करार पर भरोसा किया जिसमें उनके मतानुसार यह प्रावधान है कि समीक्षा का दायरा आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध तक ही सीमित होना चाहिए । इस मामले में यद्यपि, समीक्षा का अनुरोध चीन से हुए आयातों के बारे में किया गया है तथापि, उक्त समीक्षा उन सभी देशों (अर्थात् ताइवान और हांगकांग सहित) के संबंध में की जा रही है जिनके बारे में किसी भी हितबद्ध पार्टी ने कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया है ।
- पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और ए डी ए के अनुच्छेद 11 को उद्धृत करते हुए घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उक्त नियमों में दो तरीके से या तो किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा समीक्षा हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर या फिर प्राधिकारी की खुद की पहल पर जांच शुरू करने का प्रावधान है । यदि प्राधिकारी द्वारा किसी हितबद्ध पार्टी के

अनुरोध के आधार पर समीक्षा शुरू की जाती है तो यह स्पष्ट रहता है कि ऐसा कोई अनुरोध समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करने वाली सकारात्मक सूचना पर आधारित होना चाहिए। समीक्षा के लिए आवेदक ने यह तर्क दिया है कि किसी समीक्षा की शुरुआत हेतु सकारात्मक सूचना की जरूरत नहीं है और उसने उक्त समीक्षा हेतु कोई सकारात्मक सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

- चूंकि निर्यातक ने सत्यापन योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध किए बिना कोरे वक्तव्य का सहारा लिया है और उसने अपनी कानूनी हैसियत और शुल्क जारी रहने के दौरान उन पर शुल्क लागू होने के बारे में तथ्यतः गलत, भ्रामक, विरोधाभासी वक्तव्य दिए हैं।
- कि केवल लेखा बहियों की अंग्रेजी में उपलब्धता अपर्याप्त है। निर्यातक ने यह दावा भी नहीं किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों (सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों) का पालन करता है।
- कि याचिकाकर्तों का यह दावा कि उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आयी है, गलत है और प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए वह गलत आंकड़ों पर आधारित है।
- कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारतीय बाजार में पोटैशियम परमेगनेट का पाटन जारी रखे हुए हैं।
- कि संबद्ध वस्तु का आयात स्विट्जरलैंड जहाँ पर उत्पाद के लिए कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, जैसे स्रोतों से किया गया है जिससे पाटनरोधी शुल्क से बचाव हेतु चीन के मूल की वस्तुओं के यानान्तरण का पता चलता है। घरेलू उद्योग की सूचना के अनुसार पोटैशियम परमेगनेट सीधे चीन से और तीसरे देशों के व्यापारियों से भेजा रहा रहा है। इनमें से सबसे प्रमुख देश सिंगापुर, यू ए ई, ईरान और स्विट्जरलैंड हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि वर्तमान समीक्षा हर प्रकार से पूर्ण समीक्षा है इसलिए वर्तमान जांच सिंगापुर, यू ए ई, ईरान और स्विट्जरलैंड पर भी लागू होनी चाहिए। इसके अलावा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश इस उत्पाद के आयातों पर की जाए भले ही निर्यात का देश और उद्गम का देश संबद्ध देशों में से कोई भी हो।
- कि चीन से हुए निर्यातों की वास्तविक मात्रा आंकड़ों के संकलनकर्ता अभिकरणों द्वारा सूचित मात्रा से काफी अधिक है।
- यह कि याचिकाकर्ता न तो चीन में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है, न ही याचिकाकर्ता का भारत को हुए निर्यातों की मात्रा में सर्वाधिक हिस्सा है। चीन में संबद्ध वस्तु के लगभग 12 अन्य प्रमुख उत्पादक हैं।
- यह कि भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक थे जिनका नाम मै0 कुटी एंटरप्राइजेज लि0 पोण्डा, गोवा और मै0 सुपर इलेक्ट्रो मैगनीज कैमिकल्स, कुंदाई, गोवा था। तथापि, उन उत्पादकों ने काफी पहले अपना उत्पादन बंद कर दिया है और

यूनिवर्सल कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा० लि० इस समय भारत में उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है । चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीन से निर्यातकों ने अपना पाटन जारी रखा है और वे इस उत्पाद को भारतीय उद्योग की इष्टतम उत्पादन लागत और उचित बिक्री कीमत से कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं ।

- यह कि चीनी उत्पादक भारत समेत विश्व के अनेक देशों में अंधाधुंध पाटन कर रहे हैं । अमरीका, यूरोप और भारत पहले ही इस अंधाधुंध पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति उठा चुके हैं और चीन से पाटन के कारण यूरोप में उत्पादन सुविधाएं पहले ही समाप्त हो गई हैं । अब चीन से पाटन का उद्देश्य संबद्ध वस्तु के एकमात्र भारतीय निर्यात को समाप्त करना है ।
- यह कि पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आयोग और अमरीका द्वारा चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता रहा है । भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक मामलों में चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है । अतः इस मामले में भी चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी निर्यातकों को यही व्यवहार दिया जाना चाहिए ।
- यह कि यूनान प्रोविन्स जिआन सुई काउन्टी कैमिकल इंडस्ट्री फैक्टरी (वाईपीजेसीसीआईएफ) के निजी कंपनी होने का दावा किया गया है जबकि कंपनी ने मूल जांच के समय अपने पिछले अनुरोधों में यह दावा किया है कि यूनान प्रोविन्स एक 100% राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है ।
- यह कि बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार और अलग-अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए अनेक अपेक्षाओं को पूरा करना होता है । प्रथमतः निर्यातक के निर्णय बाजार संकेतों के अनुसार किए जाने चाहिए । दूसरे, यह निर्णय बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के लिए जाने चाहिए । तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे निर्णयों में निविष्टियों का बाजार मूल्य प्रदर्शित होना चाहिए । इस तरह के मामले में, न तो निर्यातक द्वारा दावा की गई विद्युत एवं पानी की कीमत को यथारूप में स्वीकार किया जा सकता है और न ही जब तक उपर्युक्त प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता तब तक निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जा सकता है ।
- यह कि कंपनी ने यह दावा किया है कि वे खरीदी गयी कच्ची सामग्री पर अदा किए गए मूल्यवर्द्धित कर की वापसी के हकदार हैं । तथापि तथ्य यह है कि कंपनी ने अदा किए गए अधिक वैट के संबंध में वैट की वापसी का दावा नहीं किया है ।
- यह कि मै० ग्रुपस्टार्स, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में, वाईपीजेसीसीआईएफ को उत्पाद की बिक्री करते हैं । वह उत्पाद को वाईपीजेसीसीआईएफ को बीजकीकृत करता है और वाई पी जे सी सी आई एफ से अपने भुगतान प्राप्त करना है । ग्रुपस्टार्स,

वाईपीजेसीसीआईएफ द्वारा भारतीय निर्यातकों को प्रभारित कीमत से संबंधित नहीं है। वाईपीजेसीसीआईएफ भारतीय आयातकों को उनके द्वारा बीजकीकृत वस्तुओं के आधार पर उत्पाद का प्रत्यक्ष रूप से प्रेषण करता है। गुपस्टार्स वाईपीजेसीसीआईएफ को कोई कमीशन नहीं देती है। इस व्यवस्था के कारण यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता द्वारा किस प्रकार इन सौदों को निर्यातों के रूप में माना जा सकता है।

- इसके अलावा, उस कीमत, जिस पर कंपनी वाई पी जे सी सी आई एफ को वस्तुओं की बिक्री करती है, को "निर्यात कीमत" नहीं माना जा सकता है।
- यह कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि सौदेवार आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन न किया जाए क्योंकि इन आंकड़ों में इस वस्तु की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव पाए गए थे जिनके लिए कोई कारण नहीं दिया गया था।
- यह कि उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम व्यापार हो सकता है और विक्रेता और निरपवाद रूप से दोनों देशों में कुछ एजेंट इसमें शामिल होंगे। भारत में मांगकर्ता एजेंट हैं जो उपभोक्ताओं से व्यवसाय प्राप्त करते हैं और निर्यातक देशों में अभिकर्ताओं को आर्डर देते हैं। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय एजेंट के लिए 3% की दर से और चीन में एजेंट के लिए 3% की दर से कमीशन को एफ ओ बी निर्यात कीमत से घटाया जाना चाहिए।
- यह कि समीक्षा संबंधी उपबंध के अंतर्गत पाटन और क्षति के जारी रहने या इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की अपेक्षा है और इस जांच को करते समय इस बात की भी जांच की अपेक्षा है कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि हांगकांग और ताइवान से कोई आयात नहीं हुए हैं, पाटन नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप इन स्रोतों से कोई पाटन नहीं हुआ है। चीन के निर्यात आंकड़े हांगकांग और ताइवान दोनों को इस उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात दर्शाते हैं और इसलिए इन देशों से पाटन की आशंका है।

### घ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:

10. आवेदक निर्यातक और घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न पहलुओं पर किए गए उपर्युक्त अनुरोधों के अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी कुछेक अनुरोध किए हैं जिन्हें रिकार्ड में भी रखा गया है।



### घ.3.1 चीनी ताइपेई

11. ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली और विदेश व्यापार ब्यूरो, आर्थिक कार्य मंत्रालय, ताइवान चीन गणराज्य ने प्राधिकारी के समक्ष अपने संक्षिप्त अनुरोध में कहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनीज अयस्क के बनाया जाता है और प्रायः ऑक्सिडेंट, एंटीसेप्टिक या विनिर्माण प्रक्रियाओं में ब्लीच के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज की खान के अभाव के कारण, ताइवान अपनी घरेलू खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतः पोटेशियम परमैंगनेट के आयातों पर निर्भर करता है। इस उत्पाद के उनके आयात और निर्यात आंकड़ों के अनुसार, चीन आयातों का सबसे बड़ा स्रोत है जिसने ताइवान को \*\*\*\*\* अमरीकी डालर मूल्य के उत्पाद की आपूर्ति की और उसका हिस्सा जनवरी, 1999 और जनवरी, 2004 के बीच उसके कुल आयातों का \*\*\*\* % बनता है। यद्यपि ताइवान ने अब भी कुछेक देशों को इस उत्पाद की अल्प मात्राओं का निर्यात किया है, तथापि ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान इनमें से किसी भी निर्यात का गंतव्य भारत नहीं था।
12. यह भी अनुरोध किया गया कि मूल पाटनरोधी जांच प्रक्रिया में चीनी ताइपेई की सरकार और जाँचाधीन ताइवानी निर्यातकों ने प्राधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण दिया था कि ताइवान ने जाँचाधीन अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया था। उन्होंने फिर दोहराया है कि जांच अवधि और अब के समय के बीच भारत को संबद्ध उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है। फिर भी इस उपाय के कारण उनके संभावित व्यापार हितों में गंभीर बाधा पहुंची है। अतः उन्होंने उस देश के विरुद्ध इस उपाय को रद्द करने का आग्रह किया है।

### घ.3.2 हांगकांग

13. ट्रेड एवं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार ने हांगकांग बाह्य व्यापार आंकड़ों से प्राप्त व्यापार आंकड़ों को प्रस्तुत किया है और प्राधिकारी के समक्ष अपने संक्षिप्त अनुरोध में यह तर्क दिया है कि उनके व्यापार के आंकड़ों के अनुसार हांगकांग ने वर्ष 1999 से भारत को पोटेशियम परमैंगनेट का कोई निर्यात नहीं किया है। उन्होंने आगे यह आग्रह किया है कि एडीए के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार "उन मामलों में तत्काल समाप्ति (उपायों की) होगी जिनमें प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा पर है, या यह कि पाटित आयातों की मात्रा, वास्तविक यथासंभावित, या क्षति नगण्य है" उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि उपर्युक्त निर्धारण के लिए "पाटित आयातों की मात्रा को आम तौर पर नगण्य माना जाएगा यदि

किसी देश विशेष से पाटित आयतों की मात्रा आयातक सदस्य देश में समान उत्पाद के आयातों का 3% से कम बनती हो।" अतः इस अवधि के दौरान हांगकांग से संबद्ध वस्तुओं के शून्य आयातों के मद्देनजर इस देश के विरुद्ध शुल्क को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

### घ.3.3 मै0 चांगक्विंग जियालिंग कैमिकल्स लि0 चीन जन.गण. एवं मै0 कन्हैयालाल, पुणे

14. मै0 चांगक्विंग जियालिंग कैमिकल्स लि0 चीन जन.गण. ने भारत में अपने आयातक मै0 कन्हैयालाल के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर दिया है और इसके साथ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का संक्षिप्त उत्तर दिया है। उन्होंने अपने अनुरोधों में मै0 ग्रुपस्टार्स द्वारा प्रस्तुत समीक्षा संबंधी आवेदन का समर्थन करने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं उठाया है।

### घ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) में यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वे उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है तो वे केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे।
16. करार के अनुच्छेद 11.2 में व्यवस्था है कि प्राधिकारी, जहाँ जरूरी हो, अपनी स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जिसने समीक्षा की आवश्यकता को सही ठहराते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की हो, के अनुरोध पर या बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से एक तर्कसंगत अवधि बीत गई हो, शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे। हितबद्ध पक्षकारों के पास प्राधिकारी से इस बात की जाँच करने का आग्रह करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क को हटाया या इसमें परिवर्तन किया जाता है तो क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने या इन दोनों की संभावना है। यदि इस पैराग्राफ के अंतर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की आगे कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

17. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत समीक्षा के आधारों को सही साबित करना अनिवार्य है और आवेदक ऐसा करने में विफल रहा है। अतः समीक्षा की शुरुआत त्रुटिपूर्ण है। आवेदक निर्यातक ने तर्क दिया भारतीय कानून इस दृष्टि से अपेक्षाकृत व्यापक है कि इसमें प्राधिकारी के लिए समय-समय पर शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना अपेक्षित है और इसमें समीक्षा की माँ करने वाले पक्षकार पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं डाला गया है। इस उदार स्थिति के बावजूद उन्होंने एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनेक आधारों पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराई है और समीक्षा की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उनके अनुरोधों में कोई विरोधाभास या भ्रामक सूचना नहीं है जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा आरोप लगाया गया है।
18. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जाँच की है और उनका यह विचार है कि नियम 23 में दी गई संतुष्टि की शर्तों का अर्थ उचित ढंग से जांच करने के बाद शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता के लिए प्राधिकारी की संतुष्टि है और न कि समीक्षा की शुरुआत के लिए। समीक्षा की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के पास सकारात्मक सूचना होना अपेक्षित है जिस पर प्राधिकारी यह निर्णय लेने के लिए विश्वास कर सके कि क्या शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की जाँच के लिए समीक्षा अपेक्षित है। इस मामले में आवेदक ने अपने समीक्षा संबंधी आवेदन में प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त सूचना प्रस्तुत की थी तथा प्रस्तुत की गई सकारात्मक सूचना के आधार पर समीक्षा की शुरुआत की गई थी। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए दावों और उनके विरुद्ध दावों को सही ठहराने के लिए साक्ष्यों की प्रस्तुति जाँच का विषय है और इसे जांच की प्रक्रिया के दौरान समीक्षा का आग्रह करने व पक्षकार समेत अन्य पक्षकारों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, समीक्षा का निष्कर्ष समीक्षा के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होगा। इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि यह समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सूचना के आधार पर उचित ढंग से शुरू की गई है जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है।
19. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस समीक्षा का विस्तार अन्य देशों अर्थात् चीनी ताइपेई और हांगकांग तक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समीक्षा हेतु अनुरोध चीन के एक अकेले निर्यातक ने किया था। प्राधिकारी का यह विचार है कि करार तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी पर लागू उपायों को जारी रखने की

आवश्यकता की समीक्षा करने का दायित्व है। अतः करार और पाटनरोधी नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकारी का सभी देशों को समीक्षा के दायरे में शामिल करना बाधित होता हो जबकि प्राधिकारी के पास समीक्षा को उचित ठहराने संबंधी सकारात्मक सूचना उपलब्ध है।

20. घरेलू उद्योग ने भी अपने समीक्षा आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथार्थता बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति और योग्यता के बारे में अनेक मुद्दे उठाए हैं। घरेलू उद्योग ने समीक्षा संबंधी आवेदन और अलग पाटन मार्जिन का दावा करने के लिए नए जेवी की अधिकारिता पर इस आधार पर प्रश्नचिह्न लगाया है कि वे उत्पाद के प्रत्यक्ष निर्यातक नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि अमरीकी पाटनरोधी प्राधिकरण ने यह पाया है कि इस कंपनी ने अपनी स्थिति के बारे में उनके समक्ष भ्रामक सूचना प्रस्तुत की थी।
21. इस संबंध में प्राधिकारी करार के अनुच्छेद 11.2 का संदर्भ लेते हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को समीक्षा के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा और अनुच्छेद 6.11 में निर्यातक देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए किसी समीक्षा के लिए अनुरोध करने का किसी पक्षकार का अधिकार केवल इसलिए प्रतिबंधित मालूम नहीं होता है कि उत्पादक सीधे वस्तु का निर्यात नहीं करता है और निर्यात के लिए किसी व्यापारी का प्रयोग करता है जो इस मामले में एक सहबद्ध कंपनी है जिन्होंने आंकड़ों के अपने हिस्से के लिए अधिप्रमाणिकता और प्राधिकार का प्रमाण पत्र दिया है। मूल जांच में पता लगाए गए निर्यातक के एक सहबद्ध पक्षकार होने के कारण नियम 22 के अनुसार यह पक्षकार अलग पाटन मार्जिन और शुल्क के लिए किसी नई शिपर समीक्षा के लिए प्राधिकारी को अनुरोध नहीं कर सका। तथापि प्राधिकारी का यह विचार है कि विभिन्न पक्षकारों की स्थिति और उठाए गए अन्य मुद्दों की जांच इस जांच पड़ताल की विषय वस्तु है और जांच परिणामों में उचित स्थानों पर इसका पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है। जहाँ तक अमरीका की जांच का संबंध है, प्राधिकारी का यह विचार है कि ये स्वतंत्र जांच हैं और इसलिए इनका इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं है।
22. सभी दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत परिवर्तित परिस्थितियों संबंधी सकारात्मक सूचना के मद्देनजर इस मामले में शुरु की गई मध्यावधि समीक्षा उचित है।

## ड. पाटन का निर्धारण

### ड.1 चीनी ताइपेई

23. ताइपेई इकॉनामिक एण्ड कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली और ब्यूरो ऑफ फॉरेन ट्रेड, आर्थिक मंत्रालय, ताइवान चीन गणराज्य ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया कि चीनी ताइपेई के पास पोटेशियम परमेगनेट के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ और कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है और वे अधिकांशतः चीन से होने वाले इस वस्तु के आयातों पर निर्भर हैं। ताइपेई के व्यापार आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे तर्क दिया है कि जनवरी, 1999 और जनवरी, 2004 के बीच चीनी ताइपेई ने भारत को इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया था यद्यपि इस अवधि के दौरान अन्य देशों को इस वस्तु के बहुत कम निर्यात किए गए हैं।
24. ताइपेई द्वारा प्रस्तुत व्यापार संबंधी आंकड़ों से जनवरी, 1999 और जनवरी, 2004 के दौरान ताइवान द्वारा इस उत्पाद के \*\*\*\* अम.डा. मूल्य के कुल आयातों का संकेत मिलता है और इसी अवधि के दौरान चीन से हुए आयात \*\*\*\* अम.डा. मूल्य के हुए थे। इसी अवधि के दौरान चीन ने विभिन्न देशों को \*\*\*\* अम.डा. मूल्य की संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारत के विरुद्ध कोई निर्यात होने का संकेत नहीं है। इसी अवधि के लिए भारतीय व्यापार आंकड़े निम्नानुसार आयात आंकड़े प्रदर्शित करते हैं-

कि.ग्रा.	2000-01	2001-02	2002-03	जन.-दिस.-2003
चीनी				
ताइपेई	51500	0	0	0

25. यद्यपि भारतीय व्यापार आंकड़ों में ताइवान से अल्प मात्रा में आयात हुए थे तथापि वर्ष 2000-01 के दौरान इस बात पर विचार करते हुए कि उस देश में कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, ताइपेई के प्राधिकारियों के अनुरोध के अनुसार उस देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के अलग-अलग उद्गम, अधिकांशतः चीनी मूल के, प्रतीत होते हैं। मूल मामले में लगाया गया शुल्क संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाया गया है। अतः ताइवान से निर्यातित अन्यत्र विनिर्मित वस्तुओं पर उद्गम के प्रमाण-पत्र के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा। इस मामले में यदि वस्तुओं का उद्गम चीन में है और इनका चीनी ताइपेई को निर्यात किया गया है तो

इस पर चीनी निर्यातों पर प्रयोज्य शुल्क, यदि कोई हो, लगाया जाएगा। प्राधिकारी की जानकारी में यह बात भी लाई गई है कि मूल जाँच अवधि के दौरान भी चीनी ताइपेई से कोई निर्यात नहीं हुए थे। अतः प्राधिकारी की यह राय है कि इस देश के पास भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात का कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है और इस देश से संबद्ध वस्तुओं का इस समय कोई पाटन नहीं हो रहा है, इसलिए चीनी ताइपेई के विरुद्ध शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## ड.2 हांगकांग

26. ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार ने भी यह दावा करते हुए अपने व्यापार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि वर्ष 1999 के बाद से उस देश से उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है। हांगकांग के प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत व्यापार आंकड़ों से 1999-2003 की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के शून्य निर्यातों और \*\*\*\*\* हांगकांग डालर मूल्य के पुनर्निर्यातों का संकेत मिलता है। तथापि इनमें से कोई निर्यात भारत को नहीं किया गया है। क्षति संबंधी जाँच अवधि के लिए भारत के व्यापार संबंधी आंकड़ों से हांगकांग से कोई निर्यात प्रदर्शित नहीं होता है। हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण की कोई सुविधा नहीं दिखाई देती है। अतः अन्य देशों से आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात या यानांतरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, चीनी मूल की वस्तुओं के पुनर्निर्यात या यानांतरण, यदि कोई हो, के ऐसे किसी मामले में चीन के विरुद्ध यथा प्रयोज्य शुल्क लगाया जाएगा। अतः प्राधिकारी के पास इस देश के विरुद्ध शुल्क को जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

## ड.3 चीन जनवादी गणराज्य

27. चीन जन.गण. से निम्नलिखित निर्यातकों ने समीक्षा की शुरुआत के बाद प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत किया है:

1. मै0 ग्रुपस्टार्स (युनान) एलएलसी, चीन जन.गण. उत्पादक के रूप में, मै0 वाईपीजेसीसीआईएफ के माध्यम से निर्यातक
2. मै0 चोंगक्विंग जियालिंग केमिकल्स लि0 चीन जन.गण., उत्पादक-निर्यातक

28. चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना और ऊपर उल्लिखित अलग-अलग निर्यातकों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे के मद्देनजर प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों को अलग-अलग बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या ये निर्यातक बाजार संकेतकों के अनुसार प्रचालन कर रहे हैं और उनके वाणिज्यिक प्रचालनों पर राज्य का कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं है।

### ड.3.1 बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे संबंधी जांच

क. मै0 ग्रुपस्टार्स (युनान) एवं मै0 वाईपीजेसीसीआईएफ, चीन जन.गण.

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामलों में इस मध्यावधि समीक्षा के लिए मै0 ग्रुपस्टार्स कैमिकल (युनान) चीन एल एल सी है जो पोटेशियम परमैंगनेट का उत्पादक है जोकि इस जांच में शामिल उत्पाद है। संबद्ध वस्तुओं का निर्यातक अर्थात् मै0 युनान प्रोविन्स जियान्सुई कैमिकल फैक्टरी (वाई पी जी सी सी आई एफ) ने उपरोक्त कंपनी द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात से संबंधित संगत सूचना भी उपलब्ध कराई है। याचिकाकर्ता ने मै0 ग्रुपस्टार्स एल एल सी, यूएसए, मै0 युनान प्रोविन्स जियान्सुई काउंटी कैमिकल इंडस्ट्री फैक्टरी, चीन और मै0 झौघुइ युआनटोंग इनवेस्टमेंट कन्सलटेशन सेन्टर, बीजिंग, चीन के बीच एक संयुक्त उद्यम होने का दावा किया है। तथापि, उत्पादक इस उत्पाद का निर्यात मै0 युनान प्रोविन्स जियान्सुई काउंटी कैमिकल इंडस्ट्री फैक्टरी, चीन के जरिए करते हैं।
30. समीक्षा के लिए आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दावे का विरोध किया है और तदनुसार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार विस्तृत अनुरोध प्रस्तुत किया है। बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे संबंधी इसके दावे के संबंध में आवेदक से अतिरिक्त सूचना भी मांगी गई थी और आवेदक ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी थी।
31. इन कंपनियों की शेयरधारिता पैटर्न तथा अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माता तथा निर्यातक के वाणिज्यिक निर्णय लेने में संयुक्त उद्यम के सभी तीनों भागीदारों के परिसरों में इन दावों के आधार पर सत्यापन किया गया था। इस जांच की आवश्यकता की इस मामले में गैर बाजार अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई थी तथा आवेदक द्वारा समीक्षा के लिए व्यक्तिगत व्यवहार बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा



किया गया था । निर्यातक ने अलग व्यवहार का इस आधार पर दावा किया है कि वे पूर्ण बाजार स्थिति के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं चाहे देश में सामान्य आर्थिक स्थिति कैसी भी हो और अनेक व्यावसायिक कार्यकलापों में राज्य का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा प्रभाव नहीं है । चीनी वाणिज्य मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ फेयर ट्रेड के अनुरोध पर इसमें शामिल निर्यातकों की स्थिति और कंपनियों के बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के निर्धारण के लिए अन्य मानदंडों की जांच करने हेतु उनके साथ बीजिंग में व्यापक विचार विमर्श किए गए थे । उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना जहां तक उनसे संबंधित है, पर इन जांच परिणामों में विचार किया गया है ।

32. प्राधिकारी ने नोट किया है कि समीक्षा के लिए आवेदक अर्थात् मै0 ग्रुप स्टार्स (युनान) एल एल सी, चीन ने कंपनी की स्थिति में परिवर्तन और कंपनी के प्रबंधकीय और प्रचालन पद्धतियों में परिवर्तन को देखते हुए बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा किया है । अपने दावे के समर्थन में उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि ग्रुप स्टार्स एल एल सी यूएसए, वाई पी जे सी सी आई एफ और मै0 जोघुई युआनटोंग इनवेस्टमेंट कन्सलटेशन सेन्टर बीजिंग, चीन, जिसने राज्य शासित वाई पी जे सी सी आई एफ से पोटेशियम परमैंगनेट का विनिर्माण अपने हाथ में लिया है और जो एक पूर्ण रूप से निजी उद्यम है तथा सभी सरकारी नियंत्रणों तथा निर्देशों से मुक्त है, और बाजार सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त उद्यम जे वी द्वारा चलाया जा रहा है, विभिन्न कागजात तथा तर्क प्रस्तुत किए हैं ।
33. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न पूर्व प्रकट अनुरोधों में समीक्षा शुरू किए जाने का विरोध किया और निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का इस आधार पर दावा किया है कि वर्तमान मामले में समीक्षा के लिए निर्यातक और आवेदक के पास पर्याप्त राज्य सहभागिता है जैसे कि उनके जे वी पार्टनर वाई पी जी सी सी आई एफ एक राज्य धारित उद्यम बना हुआ है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इस कंपनी ने विगत में यूएस पाटनरोधी प्राधिकारी के साथ-साथ प्राधिकारी के समक्ष बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे के लिए गलत सूचना और झूठे दावे पेश किए गए पाए गए हैं । इस संबंध में उन्होंने यूएस डी ओ सी के कतिपय जांचों को प्रस्तुत किया । उन्होंने आगे दावा किया है कि चीन को किसी भी देश में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा नहीं दिया है । तथापि निर्यातक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है चूंकि कई डब्ल्यू टी ओ सदस्यों जैसे कि अन्य के साथ साथ न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ने चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाला दर्जा पहले ही प्रदान कर दिया है । यहाँ

तक कि चीन की कई कंपनियों को भारत ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रदान कर दिया है ।

34. चीन के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के साथ-साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और समय पर की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी ने उत्पादक निर्यातक समूह को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने वाला विस्तृत प्रकटन विवरण जारी किया । तथापि, अपने पूर्व प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग प्रस्तावित बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा देने के विभिन्न आधारों पर विरोध किया है और चीन के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मै0 वाई पी जे सी सी आई एफ द्वारा दायर आवेदन के अनुवाद की गई प्रतियों के रूप में अतिरिक्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किए । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सितम्बर 2001 में वाई पी जे सी सी आई एफ द्वारा कंपनी के इंटिटी बिजनेस को उलने के पंजीकरण के लिए चीन में पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत उक्त आवेदन में उक्त बिजनेस इंटिटी ने अपने बिजनेस एकक को राज्य स्वामित्व वाला बताया है । इसलिए घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निर्यातक ने अपने अनुरोधों में प्राधिकारी को भ्रम में डाला है कि वह एक निजी स्वामित्व वाला बिजनेस एकक है । घरेलू उद्योग ने पारदर्शी और मूल्यांकन तथा निविदा पद्धति को अपनाए बिना संयुक्त स्टॉक रूट के जरिए पोटेशियम परमैंगनेट संयंत्र को निजीकरण किए जाने के बारे में अनेक तर्क दिए ।
35. अपने पूर्व प्रकट अनुरोधों और मामले की सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और साक्ष्य के रूप को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की सूचना और जटिल तर्कों को नोट किया । तथापि अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक निष्पक्ष मौका देने के लिए निर्यातक को ऊपर उद्धृत दस्तावेज उनके विचारों और पुष्टि के लिए भेजा । निर्यातक ने इस पर अतिरिक्त समय का अनुरोध किया और जहां तक संभव हो सकता है, समय दिया गया था ।
36. निर्यातक ने अपने उत्तर में प्रकटन के अंतिम स्टेज में अतिरिक्त तथ्यों का विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि पोटेशियम परमैंगनेट का निर्यातक वाई पी जे सी सी आई एफ के बिजनेस दायरे से वास्तव में हटा दिया गया था जो कि पी पी यूनिट के बिना राज्य स्वामित्व के अंतर्गत संलग्न था । आगे यह स्पष्ट किया गया कि पी पी यूनिट वाई पी जे सी सी आई एफ कर्मचारियों के द्वारा बनाये गये हैं जो पी पी बिजनेस और ग्रुपस्टार्स यूएसए के संयुक्त उद्यम से 2001 में बनी, जो बिजनेस लाइसेंस में इस बदलाव के

लिए जरूरी था। आगे यह स्पष्ट किया गया कि वाई पी जे सी सी आई एफ 7 अन्य इकाइयों के राज्य स्वामित्व के अधीन कार्यरत है।

37. तथापि निर्यातक द्वारा दिया गया उपर्युक्त स्पष्टीकरण उनके पूर्व अनुरोधों के विपरीत है कि वाईपीजेसीसीआईएफ अब एक निजी कंपनी है और यह केवल व्यापारिक कंपनी है। अपने पहले के अनुरोधों में निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वाईपीजेसीसीआईएफ का विनिवेश 1998 में शुरू हुआ और वाईपीजेसीसीआईएफ को विभिन्न सुविधाएं बाद में अन्य विभिन्न पार्टियों को बेच दी गईं तथा केवल पोटेशियम परमैंगनेट की विनिर्माण इकाई मै0 झांग गुओ यी और अन्य को वर्ष 1998 में बेच दी गई थी। तथापि वाई पी जे सी सी आई एफ का नाम पी पी यूनिट की विनिर्माण सुविधाओं के साथ जारी रहा। यह भी बताया गया कि पी पी यूनिट के अलावा इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डाइआक्साइड यूनिट, जिक प्रोडक्ट यूनिट और ड्रम मैनुफैक्चरिंग यूनिट जैसी अन्य यूनिट सरकार द्वारा अन्य निविदाकताओं को बेच दी गईं और वे अलग-अलग नाम से अपना व्यापार कर रहे हैं तथा वाईपीजेसीसीआईएफ एक निजी व्यापारी बन गया। अपने अनुरोध में निर्यातक ने वाईपीजेसीसीआईएफ को वाई पी जे सी सी आई एफ पोटेशियम परमैंगनेट यूनिट (पीपी यूनिट के कर्मचारियों के स्वामित्व वाली) से राज्य की स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में दिखाने की कोशिश की।
38. चूंकि निर्यातक के विवरण में विरोधाभास का पता चलता है इसलिए उनको संक्षिप्त प्रश्नावली भेजी गई थी ताकि वाईपीजेसीसीआईएफ (राज्य की स्वामित्व वाली इकाई) तथा वाई पी जे सी सी आई एफ (पी पी कर्मचारी वाली इकाई, यदि यह हर तरह से उस ढंग और तरीके से बनी है) के दर्जे के बारे में समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मामले का स्पष्टीकरण दे सकें। इसी एकक अर्थात् वाई पी जे सी सी आई एफ के दर्जे और दो भिन्न व्यापारिक दायरे तथा दर्जे को प्रदर्शित करते हुए उसी दिन दो व्यापारिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी किए गए तथा यह निर्यातक को इसकी सार्थकता पर तर्क देने के लिए भेजा गया था।
39. इस प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक ने 5 मई, 2005 को अपने विवरण प्रस्तुत किए। तथापि उसने स्थानीय प्राधिकरण से वाई पी सी सी आई एफ अपने साथ पी पी यूनिट के नहीं होने को प्रमाणित करने वाले प्रमाण-पत्र के अलावा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य दायर नहीं किया। प्राधिकारी द्वारा मांगा गया कोई दस्तावेज आवेदक ने अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किया। अपने उत्तर में आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न स्पष्टीकरण दिए हैं:-

- पी पी यूनिट का विनिवेश सरकार द्वारा ग्रुपस्टार्स कैमिकल (युनान) एल एल सी चीन नामक एक संयुक्त उद्यम के रूप में निजी एकक को बेचकर किया। ग्रुपस्टार्स यूएसए द्वारा 52% जेबी की शेयरधारिता, वाईपीजेसीसीआईएफ (पीपी यूनिट) के पूर्व कर्मचारियों के द्वारा 40% तथा बकाया 8% युआनटोंग इनवेस्टमेंट कंसलटेशन सेंटर द्वारा शेयरधारिता है तथा इसमें राज्य की स्वामित्व वाली वाईपीजेसीसीआईएफ द्वारा कोई शेयरधारिता नहीं है। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि पी पी बिजनेस के ब्रांड नाम जो कि पी पी यूनिट के पास का, को रखने तथा इसको उपयोग करने को जारी रखने का फैसला किया गया।
- आगे यह स्पष्ट किया गया कि व्यापारिक दायरा आदि के सभी परिवर्तन उसी रजिस्टर के अन्तर्गत किए गए इसका सीधा कारण यह था कि वाई पी जे सी सी आई एफ (सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत गैर पीपी बिजनेस) और वाई पी जे सी सी आई एफ (पीपी निजी बिजनेस) में सभी परिवर्तन काउंटी इंडस्ट्रियल और वाणिज्यिक प्रशासनिक ब्यूरो के उसी रजिस्टर में दर्ज किए गए। यह स्पष्ट किया गया है कि वाई पी जे सी सी आई एफ के लिए संदर्भ संख्या समेकित रूप में रजिस्टर संख्या है जो कि दो भागों अर्थात् सरकारी नियंत्रण और निजी स्वामित्व में विभाजित है।
- यह तर्क दिया गया है कि वाई पी जे सी सी आई एफ (सरकारी नियंत्रण इकाई) का झंग युआ यी और अन्य जिनका प्राकृतिक रूप में उनकी निजी क्षमता में जे वी के 40% शेयर है, के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट की और विनिर्माण सुविधा नहीं होने के वाई पी जे सी सी आई एफ के होंग स्टेट जियांगसुई काउंटी इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र को प्रति प्रस्तुत की है।
- यह स्पष्ट किया गया है कि पीओआई के दौरान भारत को निर्यात जेवी के पुराने बिक्री प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में वाई पी जे सी सी आई एफ द्वारा किए गए।
- आगे यह स्पष्ट किया गया है कि पीपी निर्यात व्यापार झंग गुआ यी और अन्य द्वारा लिमिटेड कंपनी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया गया।
- उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि उन्होंने वाई पी जे सी सी आई एफ के जरिए निर्यात को बन्द कर दिया है इसलिए वे वाई पी जे सी सी आई एफ के लिए अलग पाटन मार्जिन नहीं चाहते।
- निर्यातक ने आगे तर्क दिया है कि यदि वाईपीजेसीसीआईएफ राज्य की स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में कार्य करती रहती है और यह मान लिया जाए कि पीओआई के दौरान यह उद्यम संबद्ध वस्तु का निर्यात करता है तो यह आवेदक अर्थात् निर्यातक जोकि पूर्ण

रूप से संयुक्त उद्यम है, के सामान्य मूल्य निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने तर्क दिया है कि गैर अर्थव्यवस्था में उद्यम के लिए व्यक्तिगत सामान्य मूल्य के निर्धारण के समय प्राधिकारी को यह जांच करने की जरूरत होती है कि क्या यहां उद्यम का लागत उत्पादन और कीमत निर्णय को प्रभावित करने के व्यापार कार्यकलाप में सरकारी हस्तक्षेप है।

40. बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे के संबंध में चीन से घरेलू उद्योग और निर्यातक द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने के कारण प्राधिकारी ने 13 मई 2005 को दूसरा प्रकटन विवरण जारी किया जो प्रथम प्रकटन विवरण जारी होने के बाद हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए अतिरिक्त तथ्यों पर था और जो पूर्व में हितबद्ध पार्टियों द्वारा पहले से प्रस्तुत सूचना के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के आधार के लिए होगी।
41. उक्त प्रकटन के उत्तर में घरे उद्योग ने चीन से उत्पादक-निर्यातक के बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के मुद्दे पर अपनी स्थिति को दोहराया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वाई पी जे सी सी आई एफ के कानूनी दर्जे में कोई बदलाव नहीं आया और निर्यात लाइसेंस भी राज्य की स्वामित्व वाली वाईपीजेसीसीआईएफ के पक्ष में है। केवल सी पी यूनिट का जे बी में ट्रांसफर हो गया है और उत्पाद के निर्यात के सभी अधिकार राज्य के पास हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जे बी का तीसरा पार्टनर अर्थात् मै0 झांगू युआनटिंग इनवेस्टमेंट कंसलजटेशन सेंअर ही केवल मै0 झांगू गुओ यी और कुछ अन्य कर्मचारियों के ग्रुपस्टार्स द्वारा अस्तित्व में हैं। घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा तभी दिया जा सकता है जब उत्पादक और निर्यातक दोनों बाजार अर्थव्यवस्था के टेस्ट को पास कर दें। चूंकि भारत को निर्यातक एस ओ ई और ग्रुपस्टार्स के पास पी ओ आई के दौरान उत्पाद के निर्यात का कोई लाइसेंस नहीं है इसलिए उनको बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा नहीं दिया जा सकता।
42. उक्त प्रकटन के उत्तर में निर्यातक ने पुनः नियमावली 16 के अनुसार आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के बाद अतिरिक्त तथ्यों को मानने के बारे में अपनी चिंता और विरोध दोहराया है। वे अपने अनुरोधों में कतिपय विवरणों, जो कि स्पष्ट नहीं हैं, पर अपनी बात पर अडिग हैं कि एन एम ई मुद्दा सामान्य मूल्य के संदर्भ में पैदा होता है जिसका कि केवल ग्रुपस्टार्स के संदर्भ में फैसला होना चाहिए जोकि एक संयुक्त उद्यम है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि कोई उत्पादक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा कर सकता है जबकि यह भारत के निर्यात के पूर्ण श्रृंखला को स्थापित करने में समर्थ हो।

43. दूसरे प्रकटन के संदर्भ में हितबद्ध पार्टियों के विचारों, जहां तक वे इस मामले से संबंधित हैं, पर प्राधिकारी द्वारा इन निष्कर्षों में विचार किया गया और प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए पूर्व प्रकटन अनुरोधों तथा स्पष्टीकरणों को देखते हुए ग्रुपस्टार्स और वाई पी जे सी सी आई एफ को मालिकाना और बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा देने के मुद्दे की दोबारा जांच की।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

44. जांच के दौरान और चीन सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के जरिए भी प्राधिकारी के समक्ष यह अनुरोध किया गया कि वाई पी जे सी सी आई एफ का विनिवेश 1996 में शुरू हुआ और वाई पी जे सी सी आई एफ की विभिन्न सुविधाएं बाद में विभिन्न पार्टियों को बेच दी गई थी तथा 1998 में झांग गुओ यी और अन्य को केवल पोटेशियम परमैंगनेट की विनिर्माण इकाई बेची गई थी। तथापि, वाई पी जे सी सी आई एफ का नाम पी पी यूनिट की विनिर्माण सुविधाओं के साथ जारी रहा। यह भी बताया गया कि पी पी यूनिट के अलावा इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डाइऑक्साइड यूनिट, जिंग प्रोडक्ट यूनिट और ड्रम मैनुफैक्चरिंग यूनिट जैसी अन्य इकाईयां, राज्य द्वारा अन्य निविदाकर्ताओं को बेच दी गई थी और वे अलग अलग नाम से अपना व्यापार कर रहे हैं। आगे यह अनुरोध किया गया कि वाई पी जे सी सी आई एफ अब एक निजी कंपनी है और यह केवल व्यापार जारी रखे हुए है। तथापि, उपर्युक्त अनुरोधों में यह बताया गया है कि वाई पी जे सी सी आई एफ इसकी सूची के अधोलिखित बिजनेस के साथ राज्य के स्वामित्व वाली इकाई के रूप में कार्यरत है: अकार्बनिक साल्ट का विनिर्माण और बिक्री, जिंग सल्फेट, एक्टिव जिंक आक्साइड, मैगनीज सल्फेट, इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डाइऑक्साइड इत्यादि। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया कि पोटेशियम परमैंगनेट बिजनेस वाई पी जे सी सी आई एफ के बिजनेस दायरे से 7 दिसम्बर 2001 के संशोधन द्वारा बंद कर दिया गया था।
45. दिनांक 18.6.04 के उनके अनुरोध के अनुसार आवेदक ने रजिस्ट्रेशन संख्या 5325241000451 की प्रति के साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन तथा इसकी अनुवादित प्रति प्रस्तुत की और दावा किया कि वाई पी जे सी सी आई, मै0 झांग गुओ यी की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह बिजनेस लाइसेंस दि0 7.12.2001 को संशोधित हुआ था। इस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिया गया बिजनेस दायरे में रासायनिक उत्पादों का उत्पादन और बिक्री तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्यात, कच्चे माल का आयात और उत्पादन इत्यादि के लिए उपकरण के आयात शामिल है।

46. घरेलू उद्योग ने ऐसे ही बिजनेस दायरे के साथ समान रजिस्टर्ड कैपिटल को प्रदर्शित करते हुए तथा समान संख्या वाले समान दिनांक के संशोधित रजिस्ट्रेशन बिजनेस सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत की है। तथा, एक जैसा व्यापारिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की स्थिति को दर्शाता है।
47. आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सत्यापन के दौरान चूंकि नए संयुक्त उद्यम अर्थात् मै0 ग्रुप स्टार्स केमिकल युनान चीन एल एल सी के पास पोटेशियम परमैंगनेट का अपेक्षित निर्यात लाइसेंस नहीं था, तथापि निर्यात वाई पी जे सी सी आई एफ के अपने निर्यात लाइसेंस के जरिए किए गए थे।
48. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान निर्यातक द्वारा अनुरोध किया गया था कि काफी पहले वर्ष 1998 में संयुक्त स्टॉक रूट के जरिए पोटेशियम परमैंगनेट इकाई के निजीकरण की कोशिश की गई थी। तथापि, परिगणित संपत्ति मूल्यांकन के 100% तक के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की असमर्थता के कारण, कंपनी को केवल 40% की इक्विटी पोटेशियम परमैंगनेट के कर्मचारियों द्वारा ले ली गई और बाकी 52% तक जे वी के अन्य सहयोगी पार्टनर ग्रुप स्टार्स एल एल सी, यू एसए और मै0 झौगुई युआनटोंग इनवेस्टमेंट कंसलटेशन सेन्टर बीजिंग, चीन में बंट गई। तथापि, आवेदक ने अने सभी अनुरोधों में बताया है कि संयुक्त उद्यम वाई पी जे सी सी आई एफ, ग्रुप स्टार्स एलएलसी यूएसए और झौगुई युआनटोंग इनवेस्टमेंट कंसलटेशन सेन्टर, बीजिंग चीन के बीच बनाई गई थी। आवेदक ने इस तर्क के समर्थन में जे वी में धारित मांग के शेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। यह भी पता चलता है कि वाई पी जे सी सी आई एफ सभी अन्य यूनिटों के विनिवेश के बाद आज एक निजी उद्यम के रूप में है और यह केवल ग्रुप स्टार्स द्वारा उत्पाद विनिर्माण से संबंधित व्यापारिक कार्यकलाप जारी रखे हुए है। यह भी अनुरोध किया गया था कि वाई पी जे सी सी आई एफ सभी बकाया प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए व्यापारिक कार्य जारी रखे हुए हैं।
49. तथापि, अपने बाद के अनुरोधों में निवेदक ने स्वयं में दी अनेक तरह से विरोधाभासी है। अब यह मालूम होता है कि मूल एकक अर्थात् वाई पी जे सी सी आई एफ पोटेशियम परमैंगनेट बिना विनिर्माण सुविधाओं वाली एक राज्य की स्वामित्व वाली लेकिन अन्य इकाइयों के साथ जिनका अभी तक निजीकरण नहीं हुआ है, कंपनी है। केवल पोटेशियम परमैंगनेट संयंत्र उक्त संदर्भित संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित हुई है।



निर्यातक ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि वाई पी जे सी सी आई एफ एक राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी है ।

50. इस बात की पुष्टि होते हुए कि वाई पी जे सी सी आई एफ एक ही नाम और ढंग में राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कार्यरत है, अस्तित्व की पहचान के बारे में प्रश्न पैदा होता है जोकि वाई पी जे सी सी आई एफ के नाम से अन्य दो के साथ दो जे वी पार्टनर जैसे कि ऊपर बताया गया है जे वी में मिल गई थी । आवेदक ने तर्क दिया है कि यद्यपि वाई पी जे सी सी आई एफ का नाम उक्त जे वी में उपयोग किया गया है । यह वास्तव में कर्मचारियों की संयुक्त स्टॉक धारिता है जिसमें ग्रुप स्टार्स चीन के शेयरों का 40% हिस्सा बनता है और न कि वाई पी जे सी सी आई एफ (राज्य की स्वामित्व वाली) की जोकि जे वी में मिल गई है । यदि ऐसा है तो तब निर्यातक ने स्पष्ट रूप से गलत घोषणा की न केवल कानूनी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति की अपितु अपनी कानूनी तौर पर इस संबंध में प्राधिकारी को भ्रमित किया ।
51. आवेदक ने वाई सी जे सी सी आई एफ (पीपी यूनिट) के अस्तित्व को वाई पी जे सी सी आई एफ (मूल राज्य स्वामित्व वाली) अलग करने की कोशिश की है । क्योंकि दोनों अलग इकाइयां एक ही नाम से मौजूद हैं । यह भी दावा किया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट यूनिट के कर्मचारियों ने वही नाम बनाए रखा है । ब्रांड नाम को देखते हुए वाई पी जे सी सी आई एफ जिसे उन्होंने मूल इनटिटी से ले रखा है और अन्य पार्टनरों के साथ अलग इनटिटी स्थापित की है । तथापि, यह नहीं बताया गया है कि कर्मचारियों का समूह अपने आप एक इनटिटी बना सकते हैं और मूल इनटिटी को बनाए रख सकते हैं जबकि मूल इनटिटी अपने आप में वही नाम और पद्धति जारी रखे हुए है ।
52. घरेलू उद्योग ने वाई पी जे सी सी आई एफ के व्यापार लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत की है जो आवेदक द्वारा एक उत्पाद के जैसे समान रजिस्ट्रेशन संख्या वाला है । लेकिन व्यापार के दर्जे आदि इनटिटी के रजिस्ट्रेशन संख्या व्यापार दायरा और दर्जे के संबंध में पूछताछ के अन्तर में आवेदक न आगे स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन संख्या एक फाइल संख्या है जो इनटिटी के विजनेस दर्ज और दायरे के संशोधन को दर्शाता है तथा इसलिए इसका वही नाम है जबकि व्यापार दायरा भिन्न है ।
53. आवेदक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक ही नाम से दो इनटिटियां मौजूद हैं और कौन इनटिटी वास्तव में सामान निर्यात करती है । ग्रुप स्टार्स के पास उत्पाद के लिए

निर्यात लाइसेंस नहीं है। वस्तुतः निर्यात लाइसेंस राज्य की स्वामित्व वाली वाई पी जे सी सी आई एफ के पास है जो केवल वस्तुओं का व्यापार करता है न कि वाई पी जे सी सी आई एफ (पीपी यूनिट) जैसे कि आवेदक ने बताया है। इसलिए केवल निर्यात एस ओ ई द्वारा हुए हो सकते हैं और इस तथ्य पर आवेदक द्वारा भी दबाव बनाया गया क्योंकि वह यह कोशिश कर रहे थे कि निर्यात जे वी पार्टनर वाई पी जे सी सी आई एफ ( पी पी यूनिट) के जरिए हुए थे। अपने 5 मई 2005 के स्पष्टीकरण में उन्होंने दोबारा भ्रामक विवरण दिया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पी ओ आई के दौरान निर्यात वास्तव में झांग गुओ यी और अन्य द्वारा किए गए थे, जिनका जे वी सेट अप के अन्तर्गत कोई कानूनी इनटिटी नहीं दिखाई देती। इसके बावजूद यदि इन लोगों के द्वारा जैसे कि बताया गया है व्यक्तिगत क्षमता में निर्यात किए गए तो वे वाई पी जे सी सी आई एफ के निर्यात लाइसेंस का उपयोग नहीं कर सकते जो कि एक एस ओ ई है। ऐसे ही स्पष्टीकरण में आवेदक ने पुनः बताया है कि ग्रुपस्टार्स ने पी ओ आई के दौरान वाई पी जे सी सी आई एफ के जरिए निर्यात किए थे जो कि पूर्व में वाई जी जे सी सी आई एफ द्वारा दी गई वचनबद्धताओं की पूर्ति के लिए किया गया तथा वे भविष्य में वाई जी जे सी सी आई एफ के जरिए निर्यात करने की इच्छा नहीं रखते। यह स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है कि निर्यात झांग गुओ यी और अन्य द्वारा किए गए थे।

54. यह भी नोट किया गया है कि पी पी यूनिट के कर्मचारियों द्वारा धारित 40% शेयरों के अलावा जे वी में मुख्य शेयरधारिता झांग गुओ यी की है और जे वी का निदेश है तथा इस समय वह वाई पी जे सी सी आई एफ (एस ओ ई) के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि अपने व्यक्तिगत हित की रक्षा करने के लिए झांग गुओ यी के लिए चीनी कानून में कोई कानूनी स्थान नहीं है तथ पण्य की क्रिया के दौरान इसे एस ओ ई द्वारा बनाए रखा गया।
55. आवेदक और घरेलू उद्योग के उपरोक्त अनुरोधों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच यह इंगित करते हैं कि:

- हालांकि जे वी के 40% शेयर पी पी यूनिट के कर्मचारियों के पास है। वाई पी जे सी सी आई एफ ( पी पी यूनिट) की जे वी के अन्दर अलग पहचान और आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार शामिल उत्पाद के निर्यात में इसके रोल भ्रामक हैं तथा यह किसी खास साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं।
- जहां तक वाई पी जे सी सी आई एफ के दर्जे और जे वी की स्थिति का संबंध है, आवेदक ने स्पष्ट रूप से असत्य और टेढ़ी-मेढ़ी सूचनाओं को तोड़ा-मरोड़ा है। मूल वाई पी

जे सी सी आई एफ स्वयं ही राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है और पी ओ आई के दौरान उत्पाद के निर्यात में शामिल है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी पी यूनिट के व्यापार/ट्रांसफर के दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं कि वाई पी जे सी सी आई एफ (एस ओई) जे वी की सहयोगी कंपनी है।

- आवेदक ने आगे प्राधिकारी को भ्रम में डाला है कि पी ओ आई के दौरान निर्यात आवेदक से संबंध निजी कंपनी द्वारा प्रभावित थे जो सत्य नहीं है। निर्यात स्पष्ट रूप से एस ओ ई के जरिए हुए हैं। निर्यातक और इसके दर्जे के बारे में कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- झांग गुओ यी एस ओ ई के जैसे ही जे वी के सामान्य कारक हैं और इनटिटी में उसके शामिल होने से उनके संबंध हर तरह से भ्रामक हैं। कभी उसे वाई पी जे सी सी आई एफ (एस ओ ई) का प्रतिनिधि बताया जाता है और कभी उसे वाई पी जे सी सी आई एफ (पीपी) यूनिट का प्रतिनिधि बताया जाता है।

56. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समीक्षा के लिए आवेदक ने मै0 युनान प्रोविन्स जियानसुई कैमिकल कंपनी नाम वाली राज्य स्वामित्व वाली कंपनी के पोटेशियम परमैंगनेट संयंत्र जोकि वर्ष 2001 में नी संयुक्त उद्यम वाली कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी तथा मूल कंपनी इसी नाम से झांग गुओ यी और कंपनी के कर्मचारी द्वारा अधिक शेयर धारिता के साथ निजी हाथों में ट्रांसफर कर दी गई थी तथा अप्रैल 2001 से दोनों कंपनियां अर्थात् ग्रुपस्टार्स (युनान) एल एल सी चीन और मै0 वाई पी जे सी सी आई एफ क्रमशः संयुक्त उद्यम कानून और चीन कंपनी कानून के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के रूप में प्रचालन जारी रखने के लिए अपनी बात मनवाने हेतु प्राधिकारी को स्पष्ट तौर पर भ्रम में डाला है। उपर्युक्त अनुरोध स्पष्ट तौर पर यह बात स्थापित करते हैं कि समीक्षा के लिए आवेदक ने वाई पी जे सी सी आई एफ के दर्जे के स्वीकार करने के लिए प्राधिकारी को भ्रम में डाला है जैसे कि यह आज निजी उद्यम के रूप में मौजूद हो।
57. उपरोक्त के अलावा यह भी नोट किया गया कि वाई पी जे सी सी आई एफ के निर्यात प्राप्ति ग्रुपस्टार्स द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात ग्रुपस्टार्स से इसके वैट क्रय कीमत भुगतान से कम रहा है क्योंकि कारण यह है कि इस मामले में निर्यातक को वैट पुनर्भुगतान नहीं होता है। यह हानि वैट के कारण हुआ है और अन्य एस जी ए खर्च निर्यात द्वारा किए गए हैं जो कि स्पष्टतौर पर राज्य की स्वामित्व वाले उद्यम हैं।

58. जे वी का दर्जा भी स्पष्ट नहीं है इसके मद्देनजर कि एक ओर जहां जे वी के दस्तावेज वाई पी जे सी सी आई एफ को जे वी के 40% का हिस्सेदार होना प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर शेयर सर्टिफिकेट यह प्रदर्शित करता है कि यह 40% पी पी यूनिट के कर्मचारियों के पास हैं ।
59. आवेदक द्वारा जांच के दौरान प्रस्तुत भ्रामक सूचना और गलत घोषणा पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और दोनों इनटिटियों की अन्य व्यापारिक क्रियाकलापों में व्यापक तौर पर सरकारी दखल को पूरी तरह मना नहीं किया जा सकता । इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि उपर्युक्त परिस्थितियों में व्यक्तिगत बाजार अर्थव्यवस्था उत्पादक निर्यातक को नहीं दिए जा सकते । तदनुसार इस निर्यातक के सभ् निर्धारण गैर बाजार अर्थव्यवस्था आकलन और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हैं ।

**ख) मै0 चौगविवंग जियालिंग कैमिकल्स लि0 पी आर चीन**

60. मै0 चौगविवंग जियालिंग कैमिकल्स लि0 पी आर चीन ने मै0 कन्हैयालाल एण्ड कं0 पुणे के जरिए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है । तथापि, प्रश्नावली का अन्तर अधूरा पाया गया है क्योंकि निर्धारित प्रश्नावली के कई परिशिष्ट में उत्तर के सा जानकारी नहीं दी गई है । आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रश्नावली का पूर्ण और सार्थक उत्तर देने में असमर्थ रहा है जबकि उन्हें बाद में कंपनी की कमियों के संबंध में टिप्पणी भेजी गई थी । उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने न ही उनके बाजार अर्थव्यवस्था वाले दावे और न ही सामान्य प्रश्नावली उत्तर विवरण स्वीकार किए हैं । इसलिए चीन से उपरोक्त नाम के निर्यातक को इस जांच के प्रयोजनार्थ असहयोगी के रूप में माना है और इसके द्वारा दिए गए विवरण खारिज कर दिए हैं। तदनुसार इस निर्यातक के संबंध में सभी निर्धारण गैर बाजार अर्थव्यवस्था अनुमान और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित हैं ।

**ड.3.2 सामान्य मूल्य का निर्धारण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन, पी आर चीन**

**ड.2.1 सामान्य मूल्य: चीन से सभी निर्यातक**

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने अपनी व्यापार बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण और उक्त उद्देश्य के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने का अनुरोध किया है जिसे पूर्व में दर्ज किए गए कारणों को देखते हुए खारिज कर दिया है । मध्यावधि समीक्षा का उत्तर केवल दूसरे निर्यातक जिसने आंशिक उत्तर दिया वह मै0

चोंगक्विंग जियलिंग कैमिकल्स लि०, पी आर चीन है । तथापि इस निर्यातक द्वारा दिए गए आंकड़े अधूरे हैं और निर्यातक पर्याप्ततः गैर बाजार अर्थव्यवस्था के उपयुक्त नहीं है । इसलिए निर्यातक को प्राधिकारी ने असहयोगी घोषित किया है । चीन से किसी अन्य निर्यातक ने कोई अनुरोध नहीं किया है । चूंकि कोई उत्तरदाता निर्यातक पाटनरोधी नियमावली के परिशिष्ट I के पैराग्राफ 8 के अनुसार व्यक्तिगत सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने की शर्तें पूरी नहीं करता है अतः प्राधिकारी ने निर्यातक के देश में कच्चे माल की कीमत के आधार पर पाटनरोधी नियमों के अनुच्छेद I के पैरा 7 के अनुसार सभी चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जो उत्पादन के लागत पर \*\*\*% के लाभ मार्जिन पर प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित उपयोगिता और अन्य सम्मिलित लागत पर आधारित है । सभी निर्यातकों के लिए आकलित सामान्य मूल्य \*\*\*\* मी.टन के रूप में निकाली गई है ।

### ड. 3.2.2. निर्यात कीमत: मै० ग्रुपस्टार्स एलएलसी चीन

62. मै० ग्रुपस्टार्स और वाई पी जे सी सी आई एफ ने अपने समेकित अनुरोधों में जांच अवधि के दौरान भारत को उनके निर्यातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है । ग्रुपस्टार्स ने वाई पी जे सी सी आई एफ को 11 खेतों की आपूर्ति की है और वाई पी सी सी आई एफ ने भारत को 230 मी.टन के इन 11 खेतों का निर्यात किया है । पूर्व के प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उत्पादक अर्थात् मै० ग्रुपस्टार्स (युनान) एल एल सी ने जांच अवधि के दौरान भारत को एक भी खेप का निर्यात नहीं किया है, इसलिए इसे पहले तो निर्यातक ही नहीं माना जाना चाहिए । उन्होंने तर्क दिया है कि ग्रुपस्टार्स ने मै० वाई पी जे सी सी आई एफ व्यापारी निर्यातक को आपूर्ति की है, ने अपने अनुरोधों में घरेलू बिक्री कहा है । इसलिए उन्हें अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जा सकता । प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है और यह भी नोट किया कि इस मामले में वास्तविक पहचान और निर्यातक का दर्जा के विषय में काफी भ्रम है । हाल ही के मामले में उत्पादक ने एक भी खेप का पी ओ आई के दौरान भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है । मै० ग्रुपस्टार्स ने बताया है कि पीओआई के दौरान उन्होंने कोई सीधा निर्यात नहीं किया है क्योंकि भारत में उनके पास निर्यात लाइसेंस नहीं है और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण होना चाहिए । उन्होंने बताया है कि उन्होंने कभी कोई विशेष निर्यातक नहीं चुना है । जहां तक निर्यात आपूर्ति की श्रृंखला बनाए जोन का प्रश्न है, प्राधिकारी उत्पादक के फैक्टरी गेट पर निर्यात कीमत का हमेशा निर्धारण कर सकते हैं । उन्होंने उत्पादक के

लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के पहले के उदाहरण दिए । प्राधिकारी ने इस मामले की जांच की और इस मत पर पहुंचे कि जबकि निर्यात कीमत फैक्टरी गेट पर निकाली जा सकती है तो इसमें कोई कारण नहीं है कि उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन क्यों नहीं निकाला जा सकता यदि वे सीधे निर्यात करना चाहते हैं । आवेदक ने यह स्पष्ट किया है कि वे अब आगे वाई पी जे सी सी आई एफ के जरिए निर्यात जारी नहीं करना चाहते और वाई पी जे सी सी आई एफ के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन की जरूरत नहीं है । इसलिए चीन पी आर के लिए निर्यात कीमत और आकलित सामान्य मूल्य के आधार पर आवेदक के लिए अलग पाटन मार्जिन निकाला है ।

63. अपने पूर्व के प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग ने व्यापारी के निवल फैक्टरीगत निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए आवेदित समायोजनों से संबंधित चिंताओं के पर्याप्त कतिपय मुद्दों को भी उठाया है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि व्यापारी के एस एण्ड डी खर्च और सही लाभ मार्जिन को निर्यात कीमत में से घटाना चाहिए ताकि निवल निर्यात कीमत पर पहुंचा जा सके । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात एक संबद्ध पार्टी के जरिए हुए जोकि एक राज्य की स्वामित्व वाला उद्यम है । इसलिए इस संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क सही है और \*\*\*% के लाभ मार्जिन को निर्यात कीमत से घटाने की जरूरत है ताकि निवल निर्यात कीमत पर पहुंचा जा सके । यह लाभ मार्जिन व्यापारी द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष एस एण्ड डी खर्चों को पर्याप्ततः कवर करेगा । सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि निर्यातक ने भारत को निर्यात बिक्री व्यापार पर वैट रिफण्ड का दावा नहीं किया है । इसलिए वैट के लिए समायोजन निर्धारण के प्रयोजनार्थ नहीं माना गया है ।

64. तदनुसार वाई पी जे सी सी आई एफ की वास्तविक सी आई एफ निर्यात कीमत (वैट का नेट) के आधार पर अन्तर्देशीय और समुद्री भाड़ा, भण्डारण और हैंडलिंग प्रभारों, बीमा इत्यादि तथा ग्रुपस्टार्स के कारखानागत स्तर तक इसे लाने के लिए निर्यातकों के रिकॉर्डों के अनुसार जैसे कि ऊपर बताया गया है, के अनुसार व्यापारी के लिए उचित लाभ मार्जिन निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है ।

### ड. 3.2.2 निर्यात कीमत: चीन पी आर से सभी अन्य निर्यातक

65. मै0 कन्हैयालाल, पुणे ने अपने प्रकटन बाद एक अनुरोध में बताया है कि यद्यपि मै0 चोंगक्विंग जियालिंग कैमिकल्स लि0 पी आर चीन ने जांच में उचित सहयोग नहीं किया है अतः सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस

आवेदक पर लागू हो। उन्होंने भारत को निर्यातों के पण्यवार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इन्हें उनके लिए अलग पाटन मार्जिन और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच की और उनका विचार है कि संबंधित निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है और वे अपने निर्यात विवरणों के साथ अपने आंकड़ों को सत्यापित नहीं करवा सके। इसलिए बिना सत्यापन के निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुसार निर्यात कीमत को स्वीकारना संभव नहीं है। तदनुसार सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण परिवहन, समुद्री भाड़ा, कमीशन पश्चात डी एस जी सी आई एस से न्यूनतम पण्य मूल्य के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत \*\*\* अम.डा. प्रति मी.टन निकाली गई है।

निर्यात कीमत गणना						
	बिक्री वैट के साथ	बिक्री वैट का नेट	एफओबी से पहले समायोजन	एफओबी के बाद समायोजन	कुल समायोजन	निवल निर्यात कारखानागत
वाईपीजेसीआईएफ के साथ ग्रुपस्टार्स	****	****	****	****	****	****
अन्य	****	****	****	****	****	****

### ड. 3.2.3 पाटन मार्जिन

66. परिकलित सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन के निर्धारण के कारखानागत स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत से की गई है। चीन से निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निकाली गई है:

पाटन मार्जिन गणना				
	कंस्ट्रक्टिड सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
ग्रुपस्टार्स वाईपीजेसीसीआईएफ के साथ	****	****	****	54.93%
अन्य	****	****	****	66.95%



67. चीन के सभी निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक पाया गया है।

## च. क्षति का निर्धारण

### च.1 क्षति का संचयी आकलन

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस अवधि के लिए क्षति की जांच की जा रही है, उस अवधि में चीनी ताइपेई और हाँगकाँग से कोई पाटित आयात नहीं हुए हैं और इस समीक्षा में मात्र चीन से पाटित आयातों की जाँच की जा रही है अतः इस मामले में क्षति के संचयी आकलन का कोई मुद्दा नहीं है।

### च.2 क्षति का जारी रहना

#### च.2.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

69. घरेलू उद्योग का तर्क है कि शुल्क लगाए जाने के बाद भी उसे चीन से हो रहे लगातार पाटन के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। यद्यपि शुल्क लगाए जाने के बाद अस्थायी रूप से आयातों की मात्रा में कमी हुई थी। तथापि अत्यधिक पाटन के कारण उसकी मात्रा फिर बढ़ गई है।
70. निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में यह दावा किया था कि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता था कि घरेलू उद्योग को कथित पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि अपने अनुरोधों में यूनिवर्सल ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2000-2001 तथा जांच अवधि के बीच इसकी बिक्री मात्रा लगभग 33% तक बढ़ गई है तथा इनका बिक्री मूल्य 17% तक बढ़ा है। तथापि उनकी घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट का कारण चीन से आयात नहीं हैं वरन जिसमें कीमतों को एक निश्चित स्तर पर रखने का उनका अपना निर्णय है जैसा कि उनके अपने अनुरोधों में प्रदर्शित है। उनका उत्पादन तथा क्षमता उपयोग एवं बाजार हिस्सा जांच अवधि के दौरान बढ़ा है जिससे पता चलता है कि कोई क्षति नहीं हुई है। सारांशतः हितबद्ध पार्टियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में सुधार किया तथा इस समय उसे कोई क्षति नहीं हुई है तथा यदि कोई क्षति हुई है

तो इसका कारण उनकी अपनी अक्षमता है और इसलिए इन स्रोतों से आयात इसका कारण नहीं हो सकता है।

## च.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

71. प्राधिकारी ने विभिन्न पार्टियों द्वारा उनके अनुरोधों में उठाए गए विभिन्न तर्कों को ध्यान में रख लिया है तथा घरेलू उद्योग को सतत क्षति के मुद्दे की प्राधिकारी के समक्ष दी गई दलीलों के परिप्रेक्ष्य में जांच की गई है।
  72. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयतों की मात्रा तथा समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयतों का प्रभाव, तथा (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में इन आयातों का ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, की वस्तुनिष्ठ जांच के लिए प्रावधान है। प्राधिकारियों से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या आयातों में भारी वृद्धि हुई है चाहे वह निरपेक्ष रूप से अथवा आयातक सदस्य के उत्पादन अथवा खपत की तुलना में है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारियों से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटित आयातों द्वारा आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से भारी कीमत कटौती हो रही है, अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त स्तर तक अन्यथा कीमत ह्रास हो रहा है, अथवा कीमत वृद्धि में बाधा हो रही है जोकि अन्यथा पर्याप्त स्तर तक पहुँच गई होती।
  73. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभावों की जांच की तथा कीमतों एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभावों की क्षति की विद्यमानता तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, का परीक्षण करने के लिए जांच की।
  74. चूंकि चीन से निर्यातों के लिए धनात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है इसलिए उन देशों से समूचे निर्यातों को क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंधों की जांच करने के लिए पाटित आयात की तरह माना गया है।
- (क) मात्रात्मक प्रभाव: पाटित आयातों के कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव
75. संबद्ध देश से पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव तथा साथ ही साथ अन्य देशों से आयातों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

## i) आयातित मात्रा तथा संबद्ध देशों का हिस्सा:

76. घरेलू उद्योग ने असंभावित स्रोतों से आयातों की कीमतों और संकेतकों में अतार्किक विचरणों के कारण डीजीसीआई एंड एस द्वारा यथा सूचित आयात संबंधी आंकड़ों में यथार्थता के मुद्दे को उठाया था। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस के विनिमय स्तर संबंधी आंकड़ों की जांच की है। तथापि, आंकड़ों को अस्वीकार करने हेतु आवश्यक कोई प्रमुख विचलन इनमें नोट नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी ने आंकड़ों को असंबंधित विनियमों के कुछ आंकड़ों की छंटाई के बाद स्वीकार किया है। विचाराधीन उत्पाद के आयात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं -

मात्रा मी.टन में

कुल आयात एवं कुल आयात में हिस्सा								
2000-2001			2001-2002		2002-2003		जन.-दि., 2003	
	मात्रा	हिस्सा	मात्रा	हिस्सा	मात्रा	हिस्सा	मात्रा	हिस्सा
चीन	753.407	92%	85.5	81%	200	59%	336	69%
अन्य	12.754	2%	20.05	19%	141.868	41%	149.968	31%
कुल	766.161		105.55%		341.868		485.968	

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़े

77. आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2001 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद चीन से आयात वर्ष 2000-2001 में कुल आयातों के 92% से पर्याप्ततः घटकर 2001-2002 में 81% तथा 2002-2003 में 59% रह गए। तथापि, जांच अवधि के दौरान आयात निरपेक्ष रूप से तथा आयातों के सापेक्ष पर्याप्ततः बढ़कर पुनः 69% हो गए।

## ii) मांग, उत्पादन तथा बाजार हिस्सा

### (क) घरेलू उद्योग का उत्पादन

मात्रा मी.टन में

विवरण	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
क्षमता	2400	2400	2400	2400
उत्पादन-मात्रा	2039	2125	2356	2516
प्रवृत्ति	100.00	104.18	115.53	123.38
क्षमता उपयोग	85%	89%	98%	105%

78. घरेलू उद्योग के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन को आधार वर्ष की तुलना में बढ़ाया है यद्यपि इस अवधि के दौरान कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई है। क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है तथा कंपनी इसकी संस्थापित क्षमता के ऊपर प्रचालन कर रही है। तथापि, उत्पादन की घरेलू बाजार में मांग तथा घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में बिक्री करने की क्षमता के संदर्भ में भी जांच की जानी है।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्री

मात्रा मी.टन में

विवरण	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
बिक्री (घरेलू)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	108.66	112.90	119.86
बिक्री(निर्यात)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	117.25	127.71	153.58
बिक्री-कुल	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	112.02	118.68	133.03

79. उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि यद्यपि उत्पादन में 23% की वृद्धि हुई है; घरेलू बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री में मुख्य वृद्धि निर्यात खण्ड में हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू बाजार में अलाभकारी कीमत ने उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए बाध्य किया है।

(ग) मांग तथा बाजार हिस्सा

मात्रा मी.टन में

विवरण	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
घरेलू मांग	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	69.46	83.80	95.13

मांग में हिस्सा				
घरेलू उद्योग	59.06%	92.39%	79.57%	74.42%
चीन	37.72%	6.16%	11.95%	17.68%
चीनी ताइपेई	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%
हांगकांग	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संबद्ध देश	40.30%	6.16%	11.95%	17.68%
आयातों का हिस्सा	40.94%	7.61%	20.43%	25.58%

80. वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक गिरावट के बाद विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग जांच अवधि के दौरान काफी मात्रा में बढ़ी। मांग के घरेलू उद्योग के हिस्से में शुल्क लगाने के बाद वृद्धि के पश्चात गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जबकि इसी अवधि के दौरान चीन का हिस्सा काफी मात्रा में बढ़ा।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

81. चीन से पाटित आयातों के आधार पर घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई हों, के संबंध में जांच की गई।
82. इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भारित औसत उत्पादन लागत, भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) तथा घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना को मानकीकृत करने के पश्चात परिकलित) की संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत के साथ तुलना की गई है।

(i) कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव

विवरण		2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
विवरण	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100.00	100.00	100.52	100.75
बिक्री मूल्य	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	100.00	99.67	98.43
पहुँच मूल्य (बगैर पाटनरोधी शुल्क)	रु./मी.टन	****	****	****	****
कीमत कटौती	रु./मी.टन	****	****	****	****
% कीमत कटौती		5-15%	5-15%	5-20%	5-20%
क्षति रहित कीमत	रु./मी.टन				****
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन				****
% कम कीमत पर बिक्री	%				5-25%

83. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) में काफी गिरावट प्रदर्शित होती है। कीमत कटौती का निर्धारण समूची जांच अवधि के दौरान चीन से पाटित आयातों के

भारित औसत पहुँच मूल्य की इसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के भारत औसत निवल बिक्री वसूली से तुलना करके किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य संबद्ध देश से आयात कीमतों के डीजीसीआईएंड एस आंकड़ों में सूचित मूल्य में 1% हैंडलिंग प्रभार तथा प्रयोज्य आधारभूत सीमाशुल्क जोड़कर परिकलित किया गया है।

84. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित रिबेट, छूट, कमीशन तथा प्रदत्त केन्द्रीय आबकारी शुल्क पर रिबेट दी गई है।
85. कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने के प्रयोजन से चीन से आयातों की भारत औसत पहुँच कीमत की जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों तथा शेष वर्षों के लिए उत्पादन की लागत से तुलना की गई है।
86. कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री (लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना) को वास्तविक पाया गया है।

**(ii) पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण तथा मंदीकारक प्रभाव:**

87. पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण प्रभावों की उत्पादन की लागत, निवल-बिक्री वसूली तथा संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य के संदर्भ में जांच की गई।
88. संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत आधार वर्ष के पश्चात पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित करती है तथा उसके पश्चात पिछले तीन वर्षों में एक सामान्य वृद्धि प्रदर्शित करती है। तथापि, संबंधित अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट प्रदर्शित होती है जिससे घरेलू उद्योग की चीन से पाटित आयातों के कीमत प्रभावों के कारण पूरी लागत को वसूल करने के लिए अपनी कीमत को बढ़ाने में अक्षमता का पता चलता है। हितबद्ध पार्टियों ने तर्क दिया है कि चीन से शुल्क प्रदत्त आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक है तथा घरेलू उद्योग इस स्तर तक अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए मुक्त था। उनकी ऐसा करने में अक्षमता यह इंगित करती है कि बाजार ऐसी उच्च कीमतें स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को सीआईएफ आयात कीमत के साथ अपनी कीमतें अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए बेंचमार्क करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

**च.4 अन्य क्षति संबंधी मापदंडों की जांच**

89. पाटित आयातों के घरेलू उद्योग की मात्रा तथा कीमतों पर प्रभाव तथा मात्रा एवं आयातों के मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा घरेलू उद्योग की बिक्री तथा साथ ही साथ पूर्ववर्ती खण्ड में विभिन्न सेगमेंट के बाजार हिस्सों के साथ मांग के तरीकों जैसे प्रमुख क्षति संकेतकों तथा अन्य आर्थिक मापदंडों जो कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की विद्यमानता की इंगित कर सकें, का यहां निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है।

## (1) उत्पादकता

विवरण	इकाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
उत्पादकता	मी.टन/दिन	5.83	6.07	6.73	7.19
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.18	115.53	123.38

प्रति दिन उत्पादकता (वर्ष में उत्पादन के 350 दिन मानकर)

90. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की उत्पादन की अपनी श्रम उत्पादकता के रूप में मापा गया तथा नोटिस किया गया कि उत्पादन में मामूली वृद्धि तथा कार्यशक्ति में मामूली कमी के कारण उत्पादकता में सुधार आया। उद्योग ने लागत घटाने तथा प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए उत्पादकता में सुधार का प्रयास किया। तथापि, बढ़ी हुई उत्पादकता आनुपातिक रूप से लाभप्रदता में परिणित नहीं हुई।

## (ii) नकद प्रवाह पर लाभ तथा वास्तविक एवं संभाव्य प्रभाव

91. यद्यपि घरेलू उद्योग के अपने घरेलू प्रचालनों से कुल राजस्व तथा नकद प्रवाह में घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी के कारण सुधार हुआ है तथापि, उद्योग जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई वसूली में गिरावट के कारण घाटा वहन करता रहा। उद्योग पाटित आयातों की प्रचलित कीमत स्तर के कारण अपनी लागत को वसूलने के लिए उचित कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

विवरण	इकाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
लाभ					
उत्पादन की लागत	रू./मी.टन	****	****	****	****
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	****	****	****	****
लाभ/घाटा	रू./मी.टन	****	(****)	(****)	(****)
घरेलू बिक्री पर कुल लाभ/घाटा	लाख रुपए	****	(****)	(****)	(****)

## सूचीबद्ध

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
निवल बिक्री वसूली प्रति मी.टन(डीआई)	100.00	108.46	109.03	109.28



सीओपी प्रति मी.टन (डीआई)	100.00	99.69	99.36	98.13
प्रति मी.टन लाभ/घाटा	100.00	-67.98	-85.45	-114.98
लाभ/घाटा	100.00	-73.87	-96.47	-137.82

### (iii) रोजगार तथा मजदूरी

92. रोजगार स्तर में मामूली रूप से गिरावट आई है लेकिन वेतन तथा मजदूरी के कारण हुए खर्च लगभग 14% तक बढ़े हैं। तथापि, वेतन तथा मजदूरी संबंधी खर्च में वृद्धि तुलनीय अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप रही है

विवरण	इकाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
रोजगार					
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	227	237	232	225
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.41	102.20	99.12
मजदूरी					
प्रत्यक्ष श्रम	लाख रु.	162.70	171.80	197.79	198.38
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	105.59	121.57	121.93

### (iv) निवेश पर आय तथा पूंजी जुटाने की क्षमता

93. घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में आधार वर्ष तथा पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट प्रदर्शित होती है।

विवरण	इकाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
निवेश पर आय					
समूचा ब्लॉक	लाख रु.	****	****	****	****
कार्यशील पूंजी	लाख रु.	****	****	****	****
लगाई गई पूंजी(कुल)	लाख रु.	****	****	****	****
लगाई गई घरेलू पूंजी	लाख रु.	****	****	****	****
लाभ/घाटा-घरेलू बिक्री	लाख रु.	****	(****)	(****)	****
लगाई गई पूंजी पर आय	%	****	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	लाख रु.	100.00	-66.40	-93.47	-150.28

**(v) निवेश**

94. जांच अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा कोई क्षमता वृद्धि अथवा कोई नया निवेश नहीं किया गया है।

**(vi) पाटन का परिणाम**

95. पाटन का परिमाण, उस सीमा के संकेतक के रूप में जहां तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, प्रदर्शित करता है कि नामित देश के विरुद्ध निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन जांच अवधि के लिए वास्तविक है जबकि पाटनरोधी शुल्क भी लागू है।

**(vii) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

96. लगातार संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हों, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिस्थापन में प्रतिस्पर्धा की पाटित आयातों से इतर कारकों, जिनसे घरेलू बाजार की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं- के विश्लेषण के लिए जांच की गई। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है। मै0 यूनिवर्सल केमिकल्स भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए घरेलू प्रतिस्पर्धा कीमतों को प्रभावित नहीं करती हैं। अतः पाटित आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं।

**(viii) भण्डार सूची**

विवरण	इकाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003	जन.-दि., 2003
अवधि की समाप्ति पर भंडार सूची मी.टन	मी.टन	****	****	****	****
उत्पाद के % के रूप में भण्डार सूची	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	71.81	94.03	24.22

97. घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के साथ ही भण्डार सूची को परिशोधित करने में समर्थ है। तथापि, घरेलू उद्योग के निर्यात, बजाय इसकी बिक्री के भण्डार सूची परिशोधन को सहायता पहुंचाते प्रतीत हो रहे हैं।
98. उपर्युक्त आर्थिक मापदण्डों की जांच इंगित करती है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने उत्पादन तथा बिक्री मात्रा सहित बहुत से मापदण्डों में निष्पादन में सुधार किया है, तथापि यह लाभप्रदता में सुधार के रूप में परिणित नहीं हो पाया है तथा उद्योग अभी भी घरेलू प्रचालन में घाटा उठा रहा है। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है।

#### च.5 अन्य स्रोतों कारक तथा कारणात्मक संबंध

##### (i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

99. जांच अवधि के दौरान आयात चीन के अलावा केवल यूएसए और स्विट्जरलैंड से हुए हैं। तथापि इन दो स्रोतों से कुल आयात चीन से आयातों की तुलना में कम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयात कुल आयातों का 70% हिस्सा बनाते हैं तथा अन्य सभी स्रोतों से आयात शेष 30% हिस्सा बनाते हैं। जहाँ यूएसए से आयात लगभग समान कीमत स्तर पर हैं तथा स्विट्जरलैंड से आयात उच्च कीमत स्तर पर हो रहे हैं। इसलिए, ये आयात घरेलू उद्योग पर मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से पर्याप्त प्रभाव डालते प्रतीत नहीं होते।
100. इसलिए, चीन से आयातों की मात्रा तथा कीमतें घरेलू कीमतों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालती प्रतीत होती हैं तथा अन्य किन्हीं स्रोतों से आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग को पर्याप्त रूप से मौजूदा क्षति का कारण है।

##### (ii) मांग में संकुचन तथा/अथवा खपत के ढंग में परिवर्तन

101. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक गिरावट के पश्चात जांच अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई। मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में शुल्क लगाने के पश्चात की वृद्धि के बाद गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है जबकि चीन के हिस्से में इसी अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में

उत्पाद की खपत के तरीके में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग की क्षति का कारण माना जा सके ।

**(iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

102. संबद्ध वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है और घरेलू बाजार में कोई वृत्तिय प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं । मै0 यूनिवर्सल केमिकल्स देश में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है । संबद्ध वस्तुओं के आयातों का बड़ा हिस्सा चीन से होता है । इन दो बाजार शक्तियों से कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य निर्यातक देशों का भारतीय बाजार में पर्याप्त बाजार हिस्सा नहीं है । अतः घरेलू उद्योग को हुई मौजूदा क्षति के लिए व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं अथवा विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

**(iv) प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात निष्पादन**

103. पोटेशियम परमैंगनेट का उत्पादन एक उच्च प्रौद्योगिकी प्रधान प्रक्रिया नहीं है । चीन में विदेशी उत्पादक की उत्पादन सुविधा का भी सत्यापन किया गया था और यह देखा गया था कि उत्पादक समान उत्पादन प्रौद्योगिकी बल्कि पुराने संयंत्र और मशीनों का प्रयोग करते हैं । इसलिए प्रौद्योगिकी विकास अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन की अक्षम प्रक्रिया को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है ।
104. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन इसके घरेलू निष्पादन से बेहतर पाया गया था । वे निर्यात बाजार में उच्च कीमत प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं और इन वर्षों के दौरान उनकी निर्यात मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । इसलिए निर्यात निष्पादन को घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है ।

**(v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

105. श्रम उत्पादन और प्रतिदिन उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है । इसलिए उत्पादकता ऐसा कारक नहीं है जिसको घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता हो । वास्तव में घरेलू उद्योग ने उत्पादकता में सुधार के जरिए अपने घरेलू प्रचालन में घाटा कम करने का प्रयास किया है ।

106. क्षति संबंधी मापदंडों के उपर्युक्त विश्लेषण और गैर-आरोप्य कारकों की जांच से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में अनेक मापदंडों में सुधार हुआ है, फिर भी घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गिरावट, नकद घाटे और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण कीमत में कमी और मंदी के रूप में वास्तविक क्षति होना जारी है।

#### च.6 घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण

107. संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षतिरहित कीमत का परिकलन लागत प्रभाग द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के विस्तृत विश्लेषण और जांच के पश्चात किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत क्षतिरहित कीमत प्राधिका द्वारा \*\*\*\* रु. प्रति कि.ग्राम के रूप में निर्धारित की गई है।

#### च.7. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

108. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की क्षति मार्जिन के निर्धारणार्थ निर्यातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई है। संबद्ध देशों से निर्यातों की भारित औसत पहुँच कीमत और क्षति मार्जिनों का निम्नानुसार परिकलन किया गया है:

#### छ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

109. प्राधिकारी पहले ही यह पुष्टि कर चुके हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीन से पाटन जारी है और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है। इसलिए पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने शुल्क को समाप्त करने या इसमें परिवर्तन की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना की जांच की है। एडीए के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि:

\* प्राधिकारी किसी हितबद्ध पक्षकार जो समीक्षा की जरूरत को सिद्ध करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर, जहां आवश्यक हो स्वयं पहल करके शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने से उस समय तक पर्याप्त समय बीत गया हो। हितबद्ध

पक्षकारों के पास प्राधिकारियों को यह जांच करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्षति जारी रहने या पुनः होने की संभावना होगी। यदि, इस पैराग्राफ के अंतर्गत समीक्षा के परिणामस्वरूप, प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क की अब और आवश्यकता नहीं है तो इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।"

110. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति की वर्तमान दशा इस प्रकार की समीक्षा के लिए वास्तविक तथ्य नहीं है। उनका तर्क है कि किसी मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा शुल्क को जारी रखने या उसमें परिवर्तन करने या समाप्त करने संबंधी निर्णय पर पहुँचने के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित है ताकि पाटन को निष्प्रभावी किया जा सके। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध में यह तथ्य उजागर करने के लिए अनेक देशों के कानून और प्रथाओं तथा समीक्षाओं के मानकों का हवाला दिया है कि किसी समीक्षा जांच में "पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है" का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया है:

1. कि सामान्य रूप से चीन के उत्पादक और विशेष रूप से याचिकाकर्ता अब भी भारतीय बाजार में सामग्री का पाटन कर रहे हैं।
2. कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयतों के कारण लगातार क्षति हो रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति पुनः होगी अथवा इसमें वृद्धि होगी।
3. कि चीन और संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य और निर्यात कीमत में इन वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में इसमें अधिक से अधिक पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात यूएस डालर की दृष्टि से और गिरावट हो सकती थी।
4. कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण पहले गिरावट आयी और उसके पश्चात इसमें वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चीनी निर्यातक पाटन का सहारा लिए बिना भारतीय बाजार में बिक्री नहीं कर सकते हैं। जहां

तक आयात मात्राओं में अनुवर्ती वृद्धि का संबंध है, घरेलू उद्योग का यह मानना है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शुल्क मुक्त आयात छूटों का अनुचित लाभ लेकर बड़े पैमाने पर आयात किए जा रहे हैं।

5. उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, चीनी निर्यातकों ने भारत को अपनी निर्यात कीमत में कमी की है।
6. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी आयी है। वह कीमत जिस पर घरेलू उद्योग माल की बिक्री कर रहा है, एक लाभकारी कीमत नहीं है।
7. कि चीनी उत्पादकों के पास अत्यसधक अधिशेष क्षमताएं हैं और चीनी में मांग उनके द्वारा सृजित क्षमताओं से काफी कम है। यह तर्क दिया गया है कि चीन का प्रतिवर्ष 20,000 टन से अधिक का उत्पादन इसकी घरेलू खपत से काफी अधिक है और इसलिए संबद्ध वस्तुओं का अनिवार्य रूप से निर्यात किया जाएगा। अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि शुल्क को समाप्त करने से आयातों में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी।
111. प्राधिकारी ने इन सभी तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी के ध्यान में यह बात लायी गई है कि चीन से होने वाले निर्यातों पर अमरीका और ईयू में पिछले कई वर्षों से पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और ई सी में एक समीक्षा की जा रही है। इसलिए लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण अनेक बड़े बाजार पहले ही प्रभावित होने के कारण चीनी निर्यातक वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेंगे। अतः शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने की अधिक संभावना होगी।
112. इस बात की पहले ही पुष्टि की जा चुकी है कि चीन के विरुद्ध शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन हो रहा है यद्यपि इसकी मात्रा में उल्लेखनीय कमी आयी है। पाटन मार्जिन की सीमा और मौजूदा आयातों की मात्रा के साथ-साथ चीनी निर्यातों के अन्य देशों को होने वाले निर्यातों की मात्रा पर विचार करते हुए प्राधिकारी का मानना है कि यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो पाटन होना जारी रहेगा।
113. जहां तक घरेलू उद्योग को हुई क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने का संबंध है, प्राधिकारी उन कीमतों का परिक्षण किया जिन पर लागू शुल्क के बावजूद माल भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। चीनी निर्यातकों द्वारा उस समय भारी मात्रा



में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की गई है जब बिना पाटनरोधी शुल्क के मौजूदा आयातों के पहुंच मूल्य की घरेलू उद्योग की निवल बक्री वसूली और क्षतिरहित कीमत के साथ तुलना की जाती है। इस बात का कई संकेत अथवा वैध तर्क नहीं है कि शुल्क को समाप्त करने के बाद संबद्ध देशों से आयातों का कीमत ढांचा बदल जाएगा। इसके विपरीत चीन में अतिरिक्त क्षमता और मांग आपूर्ति संबंधी स्थिति को देखते हुए इस बात की अत्यधिक संभावना है कि यदि शुल्क को समाप्त किया जाता है तो कीमत स्तर में और मंदी आ सकती है जिसके कारण घरेलू उद्योग को और क्षति होगी।

### (इ) निष्कर्ष

114. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनके द्वारा किए गए अनुरोधों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के जरिए या अन्यथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसाकि उपर्युक्त जांच परिणामों में दर्ज है, की जांच करने के पश्चात तथा मौजूदा पाटन और क्षति एवं पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना संबंधी स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
  - (i) चीन गणराज्य से संबद्ध वस्तुएं इनके उचित मूल्य से कम कीमत पर आयी हैं और चीन से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन मार्जिन वास्तविक और न्यूनतम से अधिक हैं;
  - (ii) यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो चीन से पाटन के जारी रहने या पुनः होने की भी संभावना है;
  - (iii) इस समय घरेलू उद्योग को मामूली वास्तविक क्षति होना जारी है और मौजूदा क्षति मुख्यतः चीन गणराज्य से हुए पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण है;
  - (iv) यदि चीन गणराज्य से होने वाले आयातों पर से शुल्क हटा लिये जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है;
  - (v) इसलिए पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखना आवश्यक है;

(vi) क्षति जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुए हैं इसलिए चीनी ताइपेई और हांगकांग से कोई पाटन नहीं हुआ है । इन दोनों देशों में संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादन भी नहीं हुआ है । इसलिए यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो चीनी ताइपेई से पाटन के जारी रहने और/अथवा पुनः होने की कोई संभावना नहीं है । तथापि, चीनी मूल की वस्तुओं के पुनर्निर्यात अथवा यानांतरण, यदि कोई हो, को चीन के विरुद्ध लागू शुल्क के अंतर्गत समुचित रूप से कवर किया जाएगा । इसलिए इन दोनों देशों के विरुद्ध शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता नहीं है ।

**(ट) भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे**

115. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित और खुली प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः बहाल किया जा सकता है जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**(ठ) सिफारिशें**

116. इस बात का निष्कर्ष निकालते हुए कि चीन ताइपेई और हांगकांग से आयातों के बारे में पाटन और क्षति के जारी रहने की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी को इन देशों के विरुद्ध शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं मिलता और इसलिए इन देशों के विरुद्ध मौजूद शुल्क हटाने की सिफारिश करते हैं ।

117. तथापि, पाटन के लगातार सापेक्ष निर्धारण के मद्देनजर चीन पी आर से आयातों के बारे में संभावित पाटन और क्षति के साथ साथ क्षति और कारणात्मक संबंध को देखते हुए प्राधिकारी का विचार है कि उस देश से आयातों के खिलाफ लगातार उपाय किए जाने की जरूरत है । तथापि, उस देश से पाटन के वर्तमान स्तर तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करते हुए प्राधिकारी का विचार है कि चालू उपायों को संशोधित करने की जरूरत है । इसलिए प्राधिकारी निम्नानुसार बताए गए ढंग और रूप में चीन पी आर से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर आवश्यक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

18. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियमों को देखते हुए प्राधिकारी क्षति के मार्जिन के बराबर निश्चित पाटनरोशी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो इस मामले में पाटन के मार्जिन से कम हैं ताकि पाटन को रोका जा सके। घरेलू उद्योग और क्षति को समाप्त किया जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में शुल्क निश्चित कीमत आधार पर लगाए गए थे, इसलिए यह उचित मानते हैं कि निश्चित शुल्क आधार पर पाटनरोशी शुल्क लगाया जाए, तदनुसार निम्नलिखित के कालम 9 में दिए गए अनुसार निश्चित पाटनरोशी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जो चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाया जाएगा।

## ड. आगे की प्रक्रियाएं

119. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।
120. प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत उपबंधों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार निश्चयात्मक शुल्क, जैसाकि इसमें अनुशंसा की गई है, को जारी रखने, उसमें संशोधन करने या उसे समाप्त करने संबंधी जरूरत की समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए किसी अनुरोध को उस स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा अनुरोध इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर नहीं किया जाना है।

## शुल्क तालिका

क्र.स.	उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण	विशेष विवरण	उद्भव का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2841.61	पोटाशियम परमैंगनेट केएमएनओ <sub>4</sub>	सभी ग्रेड	चीन	कोई	मे0 ग्रुपस्टार यूनान, एलएलसी, चीन	कोई	285	मी.टन	अम.डा.
2	2841.61	पोटाशियम परमैंगनेट केएमएनओ <sub>4</sub>	सभी ग्रेड	चीन	कोई	कोई (उपरोक्त के अलावा)	कोई	352	मी.टन	अम.डा.
3	2841.61	पोटाशियम परमैंगनेट केएमएनओ <sub>4</sub>	सभी ग्रेड	कोई	चीन	कोई	कोई	352	मी.टन	अम.डा.

डा. क्रिस्टी फर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2005

**MID-TERM REVIEW****FINAL FINDINGS**

**Sub: Mid term review of definitive Anti-Dumping duty on imports of Potassium Permanganate originating in or exported from Peoples Republic of China, Chinese Taipei and Hong Kong**

**No. 15/2/2004-DGAD.**—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after also referred to as the ACT) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after also referred to as Rules), recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of Potassium Permanganate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China P.R., Hong Kong and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings were published vide Notification no. 46/1/2000 dated 30<sup>th</sup> December 2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 29/2001-Customs dated 12.03.2001. The Designated Authority came out with the final findings on 8<sup>th</sup> Sept 2001 and definitive antidumping duty was imposed by Customs vide Notification No: 113/2001 dated 01.11.2001 as amended by Notification No: 85/2003-Customs dated 27.05.2003.

2. **AND WHEREAS**, The Designated Authority, received an application from one of the exporters of the subject goods from China PR i.e. M/s Groupstars Chemical (Yunan) China LLC, China PR, a joint venture between Yunan Province Jianshui County Chemical Industry Factory, China PR' Groupstars Chemical LLC, USA and Beijing Zhonghui Yuantong Investment consultation Centre, Beijing for review of the antidumping duties levied on the subject goods, on the grounds of changed circumstances. On the basis of positive information submitted by the above mentioned applicant the Designated Authority considered that mid-term review of the Anti Dumping Duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the authority by the exporter. The Authority issued a public notice dated 10.03.2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping mid term review investigation under Section 9A (5) of the Act and Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is

required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

## **A BACK GROUND OF THE CASE**

3. On the basis of an application filed by the M/s Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai, the domestic producer in India, in October 2000, the Designated Authority conducted an investigation into Dumping, Injury and Causal link of the imports from the above named countries and on the basis of its determination of Dumping, Injury and Causal link, notified its final findings vide Notification No: 46/1/2000-DGAD dated 8<sup>th</sup> Sept 2001. Acting Upon the findings of the Authority the Central Government imposed antidumping duty on imports of the subject goods from the subject countries vide Customs notification No: 113/2001 dated 01.11.2001. However, the domestic industry appealed against the findings of the Designated Authority and Notification of the Central Government before the CEGAT (now renamed as CESTAT). While disposing off the petition, the Hon'ble CESTAT rejected the verification of data submitted by M/s Yunnan Province Jiangsui County Chemical Industry Factory (YPJCCIF), PR China, who participated in the investigation and declared them non-cooperative. As a result of this, the individual treatment granted to this exporter was withdrawn and exports from this company attracted residual duty. Acting upon the orders of the CESTAT, the Central Government amended the duties vide Notification No. 85/2003-Customs dated 27.05.2003. The present investigation to review the need for continuation of duty has been initiated on the basis of an application filed by one of the producers/exporters from China.

## **B. PROCEDURE**

4. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:
  - i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, alongwith the initiation notification, to all known exporters/producers in the subject countries, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;
  - ii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
  - iii) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).
  - iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.01.2003 to 31.12.2003 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2000-01 to 2002-03 and POI.

- v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
- vi)- In addition to the original applicant for the review, response to the initiation communications were received from one more exporter from China i.e. M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China, who filed its response through their representatives/importer in India.
- vii) No other exporter from any of the other countries named, have submitted any response, in any manner, to the initiation notification. However, the respective Governments of Chinese Taipei and Hong Kong made their brief submissions arguing that these countries did not export the subject goods to India.
- viii) M/s Universal Chemicals, Mumbai, the domestic producer of the subject goods and the original petitioner in the original investigation submitted its responses opposing the review;
- ix) M/s Kanhaiyalal & Co. Pune, importers of the subject goods also filed its responses to the initiation notification
- x) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xii) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- xiii) The Authority also verified the data of the cooperating exporter and applicant for the subject review, to determine the normal value and dumping margin as per the Rules.
- xiv) The Authority held a public hearing on 30.07.2004 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from China and representative of the Economic Division of Taipei Economic and Cultural Center. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;

- xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts under consideration of the Authority and the basis of determination proposed to be adopted were disclosed to known interested parties as general disclosures and confidential disclosures to parties involved vide letters dated 21<sup>st</sup> December 2005.
- xvi) A second disclosure was also issued by the Authority on 13<sup>th</sup> May 2005 including the additional facts and arguments placed before the Authority after issue of the first disclosure dated 21<sup>st</sup> December. The interested parties were required to file their comments to the second disclosure by 24<sup>th</sup> May 2005. The comments of the interested parties have been duly considered by the Authority in these findings to the extent they are relevant.
- xvi) \*\*\*\* In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

5. The product under consideration in the original investigation and the product attracting antidumping duty is Potassium Permanganate, which is an inorganic chemical. Potassium Permanganate is a dark purple crystalline material. It is a compound of manganese, potassium and oxygen. The product is odorless and soluble in water. The chemical formula of Potassium Permanganate is  $KMnO_4$ . The product is classified under custom sub-heading 2841.61 of the Custom Tariff Act, 1975. This being a changed circumstances mid-term review investigation, the investigation covers the product covered in the original investigation only. No argument has been extended, by any interested party, on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority holds that the product being manufactured by the domestic industry and the product being manufactured and exported from the subject countries are alike in all respect.

### D. Initiation of the Review and arguments raised

#### D.1 Views of the applicant for the review i.e., M/s Groupstars LLC. China

6. The application for the review has been filed by M/s Groupstars LLC, China. The applicant exporter in its original application seeking review made the following submissions:--

- That in the original investigation definitive anti dumping duties were levied vide notification no. 113/2001 dated, 1.11.2001 and the duties were imposed at the rate of US\$ 64 per MT on exports by M/s Yunnan Province Jiangshui County Chemical Industry Factory (YPJCCIF) and residual duties were imposed at the rate of US\$440 per MT for all non-cooperating exporters from PR China. However, on the basis of an appeal filed by domestic industry i.e. M/s Universal Chemical and Industry Ltd., Mumbai, CESTAT, vide order dated, 20.10.2002, treated the exporter as a non-cooperative exporter and anti dumping duty of US\$440 per MT was levied on them at par with all other exporters;



- That in the meantime the status of the exporter i.e. YPJCCIF changed and the Potassium Permanganate unit of YPJCCIF was taken over by a Sino-American joint venture formed by YPJCCIF with an American company i.e. M/s Groupstars Chemical LLC, USA as a majority share holder and M/s Beijing Zhonghui Yuantong Investment Consultation Centre, Beijing as the other joint venture partners. The new joint venture, M/s Groupstars Chemicals (Yunnan) LLC, was formed on April, 23<sup>rd</sup>, 2001 as a fully private share holding company engaged in the manufacture and marketing of Potassium Permanganate and export of the subject goods to various countries including India;
- That prohibited duties are in existence for more than three years against Chinese exports and circumstances as well as the market dynamics have undergone a significant change since imposition of such high definitive duties warranting a review;
- That in the original case the exporter i.e. M/s YPJCCIF was considered cooperative by the Designated Authority after verification of their data. However, the Hon'ble CESTAT was of the view that information provided by the company did not merit acceptance on the grounds that the information furnished by the exporter was for the calendar year i.e. from 1.1.1999 to 31.12.1999, while the period of investigation was 1.4.1999 to 31.3.2000 and the information provided in the questionnaire was insufficient and unreliable as much as the verification was also not meaningful since the books of accounts and the other official documents were in Chinese;
- That after incorporation of Sino-American joint venture, they have proper record maintenance system and the records are maintained both in Chinese as well as in English, which will make any verification or scrutiny easier and meaningful;
- That there is substantial reduction of prices of Potassium Permanganate in the international market and substantial imports are taking place into India from countries other than China at prices lower than the export prices from China;
- That landed value of Chinese exports are much higher than the selling price of domestic industry in India and prohibitive anti dumping duties against Chinese exports has caused the serious anomaly by artificially closing the Indian market to Chinese exports;
- That there has been a substantial change in the international market dynamics due to expiry of anti dumping duty on imports of Potassium Permanganate to EU from India, thereby opening up of the European market to the Indian exports and therefore, if any part of the domestic industry's production is directed towards EU market there will be a serious problem of demand supply gap in the country;
- That there has been a substantial drop of 18.5% in customs duty during the intervening period which in itself is a sufficient ground for initiation of a mid term review.

7. The domestic industry in its submissions during the course of the investigation has raised various arguments against the initiation of the review. In response to these arguments the applicants have further submitted *inter alia* that:

- That there is nothing in the Rule 23 of the Indian Antidumping Rules that requires the Designated Authority to verify, prior to initiation, that the petitioner has supplied sufficient information or evidence warranting initiation of mid term review. The Indian Rule in this context is more liberal than the obligation under

the Agreement and therefore, initiation of the review based on the request of the applicant cannot be flawed. In this connection, they have cited the decision of CESTAT in the case of M/s. Simalin Chemical Industries Vs. Designated Authority [2003 (155) ELT 51 – Del. Tr.], to argue that the Indian rules have to be interpreted in accordance with the Indian law and not the provisions of the WTO Agreement. It has also been argued that the Hon'ble Supreme Court in its various decisions has also pronounced the circumstances under which the municipal law has to be interpreted in the context of international treaties;

- That Without prejudice to the above legal position, Groupstars has given sufficient grounds in their petition necessitating the initiation of mid-term review even when no evidence or information is necessary to be given as stated above;
- They have further reiterated the grounds of review and refuted the arguments by the domestic industry that there was any misleading information in any of their submissions before the Authority.

8. In summary, the applicant has pleaded that there were sufficient grounds for a changed circumstances review of the antidumping duty in force against them and review initiated is in order.

## D.2 Views of the domestic industry:

9. The domestic industry, in its various submissions, has opposed the initiation of the review and has *inter alia* submitted:

- That the present review has been initiated without sufficient justification and based on misleading representation filed by the applicant.
- That the sole responding exporter from China (the petitioner in this case and referred to as petitioner in these submissions) did not sufficiently cooperate with the Designated Authority in the previous investigation. Besides filing of documents in Chinese language, the exporter provided almost negligible information, on the basis of which the Hon'ble CESTAT commented that the Designated Authority should have rejected the submissions made by the exporter.
- That the exporter has been found, in the past, having made false and misleading claims not only before the Hon'ble Designated Authority in India, but also before the US Department of Commerce in their antidumping investigations against the same product, because of which the US Department of Commerce, assigned the Peoples Republic of China (PRC), including Groupstar, a dumping margin of 128.94%, which is the highest margin calculated for any party in that proceeding.
- That the exporter has not provided sufficient evidence to establish, even *prima facie*, that the exporter satisfies market economy conditions. That assuming, though not admitting, that the exporter provided sufficient evidence to merit review of his dumping margin, the same does not imply review of the entire case against all countries involved. Since the request for review was from an exporter from China, review should have been restricted to the imports from China only. Domestic industry relies upon the scope of Rule 23 and Agreement on Anti Dumping, which, in their opinion, provides that the scope of review should be restricted to what has been requested for

by the applicant. In the instant case, even when the review request is in respect of imports from China, the review is being carried out in respect of all the countries (i.e. including Taiwan and Hong Kong) for which no representation has been filed by any interested party.

- Quoting Rule 23 of Antidumping Rules and Article 11 of the ADA, the domestic industry has argued that the Rules provide for initiation of investigations in two manners – either on the basis of a request for review made by an interested party or on the Authority's own initiative. In case the review is initiated by the Authority based on a request made by an interested party, it is evident that such a request must be based on positive information substantiating the need for a review. The applicant for the reviews has argued that there is no need for positive information for initiation of a review and has not furnished any positive information for the said review.
- That the Exporter has resorted to bald statement without providing sufficient verifiable evidence and has made factually incorrect, misleading contradictory statements regarding its legal status and applicability of duty on them during the currency of the duty.
- That mere availability of books of accounts in English is insufficient. It is not even the claim of the exporter that it complies with International Accounting Standards (Generally Accepted Accounting Principles).
- That the claims of the petitioners that there is a fall in the international prices of the product are wrong and based on incorrect data to mislead the Authority.
- That the producer/exporters in the People's Republic of China continue to dump Potassium Permanganate in the Indian market in spite of imposition of anti-dumping duty.
- That there has been import of the subject goods from sources like Switzerland where no manufacturing facility for the product exists and this indicates transshipment of goods of Chinese origin to avoid antidumping duty. According to domestic industry's information, Potassium permanganate is being shipped directly from China as also from the traders in third countries. Most prominent amongst these are Singapore, UAE, Iran and Switzerland. Domestic industry has argued that since the present review is a complete review into all aspects, the present investigations should be extended to Singapore, UAE, Iran and Switzerland also. Further, the anti-dumping duty may be recommended on imports of this product regardless of country of export, so long as the country of origin is any of the subject countries.
- That the actual volume of exports from China are much higher than what has been reported by the data compiling agencies
- That the petitioner is not the sole producer of the subject goods in China, nor does the petitioner command maximum quantum of exports to India. There are about 12 other major producers of subject goods in China.
- That there were two other producers of the subject goods in India namely M/s Curti Enterprises Ltd. Ponda, Goa and M/s Super Electro Manganese Chemicals, Kundai, Goa. However, these producers have suspended their production long back, and Universal Chemicals & Industries Pvt. Ltd. today

remains the sole producer of the product in India. In spite of imposition of anti-dumping duty on imports from China, the exporters from China continued their dumping and have been exporting the product at prices below optimum cost of production and fair selling price of the Indian industry.

- That the Chinese producers have been dumping indiscriminately in several countries in the world including India. Already, USA, Europe and India have suffered material injury as a result of this indiscriminate dumping and Chinese dumping has already eliminated production facilities in Europe. Now Chinese dumping is targeted at elimination of the sole Indian producer of the subject goods.
- That China has been treated as non-market economy by European Commission and United States in the past three years. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy in a number of cases. Therefore, China should be treated as a non-market economy in the instant case also and same treatment should also be extended to the exporters for determination of normal value.
- That Yunnan Province Jianshui County Chemical Industry Factory (YPJCCIF) has been claimed as a private company, whereas the company in its previous submissions at the time of original investigations claimed that Yunnan Province is a 100% State Owned Company.
- That there are a number of requirements to be satisfied to get the market economy treatment and individual dumping margin. Firstly, decision of the exporter must be in response to market signals. Secondly, such decisions must be without significant State interference. Thirdly and most importantly, such decisions must reflect market values of the inputs. Such being the case, neither, the electricity and water price claimed by the exporter can be accepted as it is, nor the exporter can be granted market economy treatment, unless the above provision is satisfied.
- That the company has claimed that it is entitled to refund of VAT paid on raw materials purchased. However, the fact is that the company has not claimed refund on account of VAT paid.
- That M/s Group stars, as the producer of the product under consideration, sells the product to YPJCCIF. It invoices the product to YPJCCIF and receives its payment from YPJCCIF. Group stars is not concerned with the price charged by YPJCCIF to the Indian exporters. YPJCCIF directly dispatches the product to the importers in India on the basis of goods invoiced by them. Group stars does not pay any commission, etc. to YPJCCIF. Because of this arrangement it needs to be demonstrated as to how these transactions can be treated as exports by the petitioner. Further, the price at which the company sells the goods to YPJCCIF can not be treated as "export price".
- That the DGCI&S data cannot be relied upon unless the transaction-wise data is carefully studies because of huge fluctuation of prices of this commodity found in this data without any reason for such huge fluctuation.
- That there can be little trade directly between the consumers and the sellers and invariably some agent in both the countries would be involved. There are

indenting agents in India, who procure the business from the consumers and places orders on the agents in the exporting countries. It is, therefore, submitted that commission @ 3% for the Indian agent and commission @ 3% for the agent in china should be deducted from the FOB export price.

- That the requirement under the review provision is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury also while examining whether continuation of duty is required to offset dumping. Such being the situation, it can not be said that merely because there are no imports from Hong Kong and Taiwan, there is no dumping. They argue that there are no imports from these sources as a result of Anti Dumping duty in force. China's export data shows significant export of this product to both Hong Kong and Taiwan and therefore, there is a potential threat of dumping from these countries.

### **D.3 Views of the other interested parties:**

10. In addition to the above submissions made by the applicant exporter and the domestic industry on various aspects, other interested parties have also made certain submissions which have also been taken on record.

#### **D.3.1 Chinese Taipei**

11. Taipei Economic and cultural Centre, New Delhi and Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, Taiwan, Republic of China in its brief submission made before the Authority submitted that Potassium Permanganate is made from manganese ore and often used as an oxidant, antiseptic or bleach in the manufacturing process. Due to the lack of manganese mine, Taiwan mainly relies on imports of Potassium Permanganate to meet the needs of its domestic consumption. According to their import and export statistics of this product, China is the largest source of import, which supplied US\*\*\*\*\* worth of the product to Taiwan and accounted for \*\*\*% of its total imports between January 1999 and January 2004. While Taiwan still exported rather small volume of this product to certain countries, none of the exports was destined for India during the above mentioned period.

12. It has also been submitted that in the course of the original anti dumping investigation, government of Chinese Taipei and the Taiwanese exporters under investigation provided clarifications to the Authority that Taiwan did not export the product to India during the investigation period. They have further reiterated that there is no export of the subject products to India between the investigation period and now. Nevertheless, their potential trade interests are seriously hindered by this measure. Therefore, they have pleaded for revocation of the measure against that country.

#### **D.3.2 Hong Kong**

13. Trade and Industry Department, Government of the Hong Kong Special Administrative Region, produced extracted trade statistics from the Hong Kong



External Trade Statistics and in their brief submission before the Authority have argued that according to their trade statistics, Hong Kong has not exported any potassium permanganate to India since 1999. They have further argued that in terms of Article 5.8 of the ADA "there shall be immediate termination (of the measure) in cases where the Authorities determine that the margin of dumping is de minimis, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible". They have also argued that for the above determination "the volume of dumped import shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped import from a particular country is found to account for less than 3 percent of imports of the like product in the importing Member". Therefore, in view of zero imports of the subject goods from Hong Kong during this period the duty against this country should be removed immediately.

#### **D.3.3 M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China, and M/s Kanheyalal, Pune**

14. M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China, filed a questionnaire response through their importer in India, M/s Kanheyalal, Pune, alongwith a brief response to the non-market economy questionnaire. They have not raised any substantial issue in their submissions except supporting the review application filed by M/s Groupstars.

#### **D.4 Examination by the Authority**

15. Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall from time to time review the need for continued imposition of anti dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.

16. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

17. The domestic industry has argued that under Article 11.2 of ADA read with Rule 23 of Indian Antidumping Rules, substantiation of grounds of review are mandatory and the applicant has failed to do so. Therefore, the initiation of the review is flawed. The applicant exporter has argued that the Indian Law is broader, in the sense that it requires the Authority to review the need for continuation of duty from time to time and does not cast an obligation on the party seeking a review to provide substantial evidence. In spite of this liberal position, they had provided positive information, as required under Article 11.2 of ADA, on several grounds and

sufficient information was available with the Authority to initiate a review. They have further argued that there is no contradiction or misleading information in their submissions as alleged by the domestic industry.

18. The Authority has examined these arguments and is of the view that the condition 'satisfaction' in Rule 23 refers to the satisfaction of the Authority of the need of continued imposition of duty after conducting a proper investigation and not for initiation of the review. What is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed sufficient information before the Authority in its review application and the review was initiated based on the positive information filed. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review. Therefore, the Authority is of the view that the review has been correctly initiated on the basis of positive information available with the Authority, which suggested that a review of the duty in force was warranted.

19. It has also been argued by the domestic industry that the review should not have been extended to other countries namely, Chinese Taipei and Hong Kong since the request for review was from a single exporter from China. The Authority is of the view that the Agreement as well the Rules casts an obligation on the Authority to review the need for continuation of the measures in force. Therefore, nothing in the Agreement or in the Antidumping Rules prevents the Authority from including all countries within the scope of the review when the positive information available with the authority suggests that such a review is appropriate.

20. The domestic industry has also raised several issues regarding the correctness of the information submitted by the applicant in their review application, their status and eligibility to get the market economy status. The domestic industry has also questioned the *locus standi* of the new JV to file the review application and claim separate dumping margin, on the grounds that they are not the direct exporters of the product. It has also been argued that the US Antidumping Authority has found that this Company had filed misleading information before them about their status.

21. In this connection the Authority turns to Article 11.2 of the Agreement which provides that any interested party shall have the right to request for a review and Article 6.11 defines a producer of the subject goods in the exporting country as an interested party. Therefore, the right of the party to ask for a review does not seem to be restricted only because the producer does not export the commodity directly and uses a trader to export, which in this case is an associate company who has provided the certificate of authenticity and authorization for their part of the data. Being an associated party to the exporter investigated in the original investigation, in terms of Rule 22 this party could not have approached the Authority for a new shipper review for a separate dumping margin and duty for itself. However, the



Authority is of the view that examination of the status of various parties and other issues raised are the subject matters of investigation and have been addressed adequately at appropriate places in the findings. As regards the US investigation is concerned, the Authority is of the view that these are independent investigations and therefore, do not have any bearing on this case. However, contradiction if any, in the data submitted by the same exporter before two different Authorities have been addressed at the appropriate places in the findings depending upon the evidences placed before the Authority.

22. Considering all arguments raised, the Authority holds that in view of the positive information on changed circumstances brought before the Authority the mid-term review initiated in this case is in order.

## **E. DUMPING DETERMINATION**

### **E.1 Chinese Taipei**

23. Taipei Economic and Cultural Centre, New Delhi and Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, Taiwan, Republic of China in their submissions have argued that Chinese Taipei does not have any raw materials required or any manufacturing facility to produce potassium permanganate and they are dependant on imports of this commodity mostly from China. Quoting the Taipei trade data they have further argued that between Jan 1999 and January 2004 Chinese Taipei did not export this product to India though they have very few exports of this commodity to other countries during this period.

24. The trade statistics submitted by Taipei indicates total imports worth US\$\*\*\*\*\* of this product by Taiwan during Jan 1999 and Jan 2004 and imports from China accounted for imports worth US\$\*\*\*\*\* during the same period. During the same period China has exported the subject goods worth US\$\*\*\*\*\* to different countries. No export is indicated against India. The Indian trade statistics for the same period shows import figures as follows:

Kgs	2000-01	2001-02	2002-03	Jan-Dec 2003
Chinese Taipei	51500	0	0	0

25. Even if the Indian trade statistics showed a small quantity of imports from Taiwan, during 2000-01 considering the fact that there is no manufacturing facility in that country, the goods exported from that country appear to have different origin, mostly of Chinese origin, as per the submission of the Taipei authorities. The duty imposed in the original case is against goods originating in or exported from the subject countries. Therefore, the goods exported from Taipei but manufactured elsewhere shall attract the antidumping duty as per the certificate of origin. In the instant case if the goods originate in China and are exported from Chinese Taipei it would attract duty applicable to Chinese exports, if any. It has also been brought to the notice of the Authority that even during the original period of investigation there was no imports from Chinese Taipei. In view of the above, the Authority is of the opinion that this country does not have any direct source to export the subject good

to India and there is no current dumping of the subject goods from this country, therefore, there is no need to continue with the duty against Chinese Taipei.

## **E.2 Hong Kong**

26. Trade and Industry Department, Government of the Hong Kong Special Administrative Region has also produced their trade statistics claiming that there is no export of the product from that country since 1999. The trade statistics submitted by the Hong Kong Authorities indicates NIL exports of domestic production and re-export worth HK\$\*\*\*\*\* during the period 1999-2003. However, none of these exports are directed against India. The Indian Trade statistics for the injury investigation period also does not show any import from Hong Kong. Hong Kong also does not seem to have any facility to manufacture the product under consideration. Therefore, re-export of goods imported from other countries or transshipment is not ruled out. However, such re-exports or transshipments, if any, of the goods of Chinese origin will, in any case, attract duty as applicable against China. Therefore, the Authority finds no reason to continue with the duty against this country.

## **E.3 Peoples Republic of China**

27. The following exporters from China PR filed their questionnaire response after initiation of the review:

1. M/s Groupstars (Yunnan) LLC, PR China as producer, exporting through M/s YPJCCIF
2. M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China, producer-exporter

28. In view of the non-market economy presumption in respect of the Peoples Republic of China, and market economy claims by the individual exporters mentioned above, the Authority has examined as to whether the responding exporters can be given individual market economy treatment. In this connection the Authority examined whether these exporters are operating under market signals and their commercial operations are not affected by any significant state intervention.

### **E.3.1 Examination of Market Economy Status**

#### **a. M/s Groupstars (Yunnan) and M/s YPJCCIF, China PR**

29. The Authority notes that applicant for this mid term review in the instant cases is M/s Group Stars Chemical (Yunnan) China L.L.C which is the producer of Potassium Permanganate, the product involved in this investigation. The exporter of the subject goods i.e. M/s Yunnan Province Jianshui Chemical Factory (YPJCCIF) has also provided the relevant information pertaining to export of the subject goods manufactured by the above named company. The applicant has claimed to be a joint venture formed between M/s Groupstars LLC, USA, M/s Yunnan Province Jianshui County Chemical Industry Factory, China, and M/s Zhonghui Yuantong Investment Consultation Center, Beijing, China. The producer, however, exports

this product through M/s Yunnan Province Jianshui County Chemical Industry Factory, China.

30. The applicant for the review has made a claim for market economy treatment and accordingly filed a detailed submission in terms of para 7 & 8 of the Annexure-I of the Antidumping Rules. Additional information was also called for from the applicant on its claim of market economy status and the applicant furnished the required information as called for.

31. On the basis of these claims verification was carried out at the premises of all the three partners of the Joint venture to examine their shareholding pattern, as well as involvement of state control, directly or indirectly, through equity holding or otherwise in the commercial decision making of the manufacturer and exporter. This examination was necessitated because of the Non Market Economy presumption in this case and Market Economy status and individual treatment claim by the applicant for the review. The exporter has claimed individual treatment on the grounds that they are operating under full market economy condition irrespective of general economic situation in the country and that there is no direct or indirect state interference or influence in their business activities. On the request of the Chinese Ministry of Commerce, Bureau of Fair Trade, detailed discussions were also held with them in Beijing to examine the status of the exporters involved and other parameters for determination of market economy status of the companies. Information provided by them in response to a detailed questionnaire, to the extent they are relevant, was considered by the Authority.

32. The Authority notes that the applicant for the review i.e. M/s Groupstars (Yunnan) LLC, China claimed market economy status in view of the changed status of the company and changed managerial and operational practices of the company. In support of their claim they produced various documents and arguments to prove that the Joint venture formed between Groupstars LLC USA, YPJCCIF and M/s Zhonghui Yuantong Investment Consultation Center, Beijing, China, which has taken over the potassium permanganate manufacturing facility from the erstwhile state-owned YPJCCIF, is a fully private enterprise free from all government controls and directions and the business of the joint venture is being carried out by the JV as per market principles.

33. The domestic industry, in its various pre-disclosure submissions, opposed the initiation of the review and the claim of market economy treatment by the exporter on the grounds that the exporter and applicant for the review in the instant case continues to have substantial state involvement as their JV partner YPJCCIF continues to be a state-owned enterprise. They also argued that this company has been found to have made false claims of market economy status and submitted misleading information before this Authority as well as the US Antidumping Authority in the past. In this regard they have produced certain findings of the US DOC. They have further claimed that no country has granted market economy status to China. However the exporter has contended that this claim of the domestic industry is factually incorrect as many of the WTO members such as New Zealand, Singapore, Malaysia, among others, have already given market economy status to

china PR. Even India has given market economy status to several companies from China.

34. Based on the information submitted by the applicant and examined during the on-the spot verification, as well as the submissions made by the Chinese Authorities, the Authority issued a detailed disclosure statement proposing to grant market economy status to the producer-exporter combination. However, in their post disclosure submissions the domestic industry contested the proposed grant of market economy status to the producer exporter combination on several grounds and produced additional information and documents in the form of translated copies of an application filed by M/s YPJCCIF before the concerned Chinese Authority. The domestic industry claimed that in the said application submitted by YPJCCIF in September 2001, before the relevant Registering Authority in China, for Registration of Alteration of Business Entity of the Company, the said business entity has declared its business ownership as 'state-owned'. The domestic industry therefore, claimed that the exporter has misled the Authority in its various submissions to accept it as a privately owned business entity. The domestic industry also made several arguments on the manner in which the erstwhile state-owned potassium permanganate plant was privatized through the joint stock route without adopting transparent and just valuation and bidding methodology.

35. Keeping in view the critical nature of the information and evidence provided by the domestic industry in its post disclosure submissions and its bearing on the case, the Authority took note of the information and the arguments of the domestic industry. However, in order to give the exporter a fair chance to defend its interests, the document referred above was sent to the exporter for their comments and confirmation. The exporter requested for additional time to comment on it and time was granted to the extent possible.

36. In their reply the exporter, while objecting to admission of additional facts at the late stage of disclosure, clarified that 'export of potassium permanganate' was actually deleted from the business scope of YPJCCIF which continued under the state-ownership without PP unit. It was further clarified that the PP unit was bought by the erstwhile employees ('YPJCCIF-Employees') of PP business and Groupstars USA to form a Joint venture in 2001, which necessitated this change in the business license. It was further clarified that YPJCCIF continues under state ownership with 7 other units.

37. However, the above clarification made by the exporter contradicted their earlier submissions that YPJCCIF is now a private Company and continues as trader only. In their earlier submissions the exporter has submitted that disinvestments of YPJCCIF started in 1998 and various facilities of YPJCCIF were sold to different parties subsequently and only the manufacturing unit of Potassium Permanganate was sold to Mr Zhang Guo Yi and others in 1998. However, the name YPJCCIF continued with the manufacturing facility of PP unit. It was also stated that apart from the PP unit other units such as electrolytic Manganese Dioxide units, Zinc product unit and drum-manufacturing units were sold to other bidders by the state and they carry out business in different names and YPJCCIF became a private trader. In their submission the exporter tried to distinguish

between YPJCCIF as a state-owned enterprise from YPJCCIF Potassium Permanganate Unit (owned by employees of the PP Unit).

38. Since the statements of the exporter appeared contradictory they were sent a brief questionnaire to clarify the issues along with supporting documentary evidence about the status of YPJCCIF (state-owned entity) and YPJCCIF (PP-Employee entity, if at all it existed in that form and manner). Copies of two business registration certificates issued on the same date showing two different business scope and status of the same entity i.e. YPJCCIF were sent to the exporter to comment and confirm the correctness of the same. Copy of this communication was also sent to the Bureau of Fair Trade (BOFT) Ministry of Commerce, Government of Peoples Republic of China for their comments.

39. In response to this query no response was received from BOFT. The exporter filed their comments on 5<sup>th</sup> May 2005. However, they failed to file any document in support of their claims except a certificate from the Local Authority certifying that YPJCCIF do not have the PP unit with it. None of the documents requested by the Authority have been furnished by the applicant along with its reply. In their reply the applicant has clarified inter alia as follows.

- PP unit was completely disinvested by the state through sale to private entities in the form of a joint venture namely Groupstars Chemical (Yunnan) LLC China. The JV had a share-holding of 52% by Groupstars USA, 40% by the former employees of YPJCCIF (PP Unit) and remaining 8% by Yuangtong investment Consultation Centre and there is no shareholding by the erstwhile state-owned YPJCCIF. It was further clarified that in order to retain the brand name associated with the PP business the employees of erstwhile PP unit decided to continue to use the same name.
- It has been further clarified that all alteration to the business scope etc. have been done under the same 'register' number for the simple reason that all changes in YPJCCIF (Non-PP business under state control) and YPJCCIF (PP private business) are recorded in the same register of County Industrial and Commercial Administration Bureau. It has been clarified that the Register No. is a reference number for YPJCCIF as a whole which has been split into two viz. State Controlled and privately owned.
- It has been argued that the YPJCCIF (state-controlled unit) has no direct or indirect control over Mr. Zhang Guo Yi and others who hold the 40% stake of the JV in their individual capacity as natural persons. They have produced a copy of a certificate purportedly issued by Honghe State Jiangsui County Industrial and Commercial Bureau certifying that YPJCCIF has no more manufacturing facility of Potassium Permanganate.
- It has been clarified that exports to India during the POI was done by YPJCCIF to honour the sales commitments prior to the formation of JV.
- It has been further clarified that PP export business is conducted by Mr Zhang Guo Yi and others without using the terminology of 'Limited Company'.

They have further submitted that they have stopped exporting through YPJCCIF and therefore, they do not want a separate dumping margin for YPJCCIF.

The exporter has further argued that even if YPJCCIF continues as a state-owned enterprise and assuming that this enterprise exported the subject goods during the POI it would not affect the normal value determination of the applicant i.e. exporter which is a fully private joint venture enterprise. They have argued that while determining individual normal value for enterprises in non-market economies the Authority is required to examine whether there is significant state interference in the business activities of the enterprise affecting its cost of production and pricing decisions.

40. Since substantial issues were raised by the domestic industry and the exporter from China in respect of the claim of market economy status a second disclosure statement was issued by the Authority on 13<sup>th</sup> May 2005 disclosing the additional facts brought before by the interested parties after issue of the first disclosure statement which will form the basis of determination by the Authority alongwith the information already furnished by the interested parties earlier.

41. In response to the said disclosure the domestic industry has reiterated its stand on the issue of market economy status of the producer-exporter from China. They have further argued that there was no change in the legal status of YPJCCIF and the export license is also in favour of the state-owned YPJCCIF. Only the PP unit was transferred to the JV and the state was holding all rights to export the product. They have also argued that even the third partner of the JV i.e. M/s Zhonghu Yuanxing Investment Consultation center is an entity floated by Mr Zhang Guo Yi and some other employees of Groupstars. The domestic industry has further argued that market economy status could be granted only if both the producer and exporter pass the test of market economy. Since the exporter to India is admittedly a SOE and Groupstar did not have any license to export the product during the POI. Therefore, market economy status cannot be granted to them.

42. In its response to the said disclosure the exporter has again reiterated its concern and objection about admission of additional facts after disclosure of essential facts in terms of Rule 16. Notwithstanding certain statements in their submissions which are not clear they have reiterated their stand that the issue of NME arises only in the context of Normal value, which is to be decided in the context of Groupstars alone, which is a private joint venture. They have further argued that a producer can claim an individual dumping margin provided it is able to establish a complete chain of exports to India.

43. The comments of the interested parties to the second disclosure to the extent they are relevant have been considered by the Authority in these findings and the Authority has re-examined the issue of ownership and grant of market economy status to Groupstars and YPJCCIF afresh in view of the post disclosure submissions and clarifications by the interested parties.



**Examination by the Authority**

44. It was submitted before the Authority during the course of the investigation and also through the submissions by the Chinese Government that disinvestments of YPJCCIF started in 1996 and various facilities of YPJCCIF were sold to different parties subsequently and only the manufacturing unit of Potassium Permanganate was sold to Mr Zhang Guo Yi and others in 1998. However, the name YPJCCIF continued with the manufacturing facility of PP unit. It was also stated that apart from the PP unit, other units such as electrolytic Manganese Dioxide units, Zinc product unit and drum-manufacturing units were sold to other bidders by the state and they carry out business in different names. It was further submitted that YPJCCIF is now a private Company and continues as trader only. However, in their above submissions it was mentioned that YPJCCIF continues as a State Owned entity with the following business in its list: Manufacture and sale of inorganic salts, Zinc sulphates, active Zinc oxide, manganese sulphate, electrolytic manganese dioxide...etc. It was also submitted that Potassium permanganate business has been taken out of the business scope of YPJCCIF vide the amendment dated 7<sup>th</sup> December 2001.

45. Vide their submission dated 18.6.04 the applicant submitted a copy of the business registration certification with registration no. 5325241000451 along with its translated version and claimed that YPJCCIF, is a privately owned company by M/s Zhang Guo Yi. This business licence was modified on 7.12.2001. The business scope indicated in this registration certificate includes production and sales of chemical products and export of potassium permanganate, import of raw material and equipment for production etc.

46. The domestic industry has submitted the copies of business registration certificate modified on the same date bearing the same number and showing same registered capital with similar business scope. However, the same business registration certificate indicates the status of the enterprise as state-owned.

47. It was also submitted by the applicant that since the new joint venture i.e. M/s Groupstars Chemical (Yunnan China LLC) did not have the requisite export licence for Potassium Permanganate the exports were routed through the erstwhile YPJCCIF under their export licence.

48. It was submitted by the exporter during the verification process that the potassium permanganate unit was attempted to be privatized through the joint stock-route way back in 1998. However, due to the inability of the employees to raise the resources to the extent of 100% of asset valuation done, the equity of the company was taken over by the employees of the potassium permanganate unit to the extent of 40% only and rest was divested to the other JV partners to the extent of 52% to Groupstars LLC, USA and M/s Zhonghui Yuantong Investment Consultation Center, Beijing, China though, the applicant has mentioned in all their submissions that the joint venture was formed between YPJCCIF, Groupstars LLC, USA and M/s Zhonghui Yuantong Investment Consultation Center, Beijing, China. In support of this argument the applicant submitted the share certificates of the employee portion of the holding in the JV. It was also understood that YPJCCIF as if

exists today is a private enterprise after divestment of all its other units and continues trading activities only in respect of the product manufactured by Groupstars. It was also submitted that YPJCCIF continues as a trading concern to complete outstanding commitments.

49. However, in their subsequent submissions the applicant has contradicted itself in many respects. Now it reveals that original entity i.e. YPJCCIF exists as a state-owned manufacturing facility without the Potassium Permanganate but with other units which have not yet been privatized. Only the potassium Permanganate plant has been transferred to the Joint Venture Company referred above. The exporter has clearly confirmed that YPJCCIF continues as a state-owned enterprise.

50. Having confirmed that YPJCCIF as an entity continues as a state-owned enterprise in the same name and form, the question arises about the identity of the entity which has entered into the JV in the name of YPJCCIF, with the other two JV partners as mentioned above. The applicant now contends that though the name of YPJCCIF has been used in the said JV it was actually the joint stock holding of the employees, which account for 40% of the shares of Groupstars China and not the YPJCCIF (State-owned entity) which has signed the JV. If that is the case then the exporter has clearly misdeclared, not only its status as a legal person, but also its legal composition.

51. The applicant has tried to segregate the identity of the YPJCCIF (PP unit) from the YPJCCIF (original state-owned entity) as if two separate entities in the same name existed. It has been contended that the employees of the erstwhile YPJCCIF Potassium Permanganate Unit had retained the same name as YPJCCIF in view of its brand name though they had already broken away from the original entity and formed a separate entity along with other partners. However, it has not been explained how a group of employees can constitute themselves as an entity and retain the name of the original entity while the original entity itself continues in the same name and style.

52. The domestic industry furnished a copy of the business license of YPJCCIF bearing the same registration number as the one produced by the applicant and it was noticed that the scope of business and the status of the entities in the said license are different. In response to the query regarding the registration number of the entities the applicant has further clarified that the registration number in fact is the file number from which the modification of the status and business scope of the entities have been done by the competent Government agency and therefore, bears the same name while the business scope is different.

53. The applicant has not clarified, assuming that two entities in the same name existed, which entity has actually exported the goods. Groupstars admittedly did not have the export licence for the product. The export licence obviously belonged to the state-owned YPJCCIF only who was trading the goods and not the YPJCCIF (PP-unit) as has been made out by the applicant. Therefore, the exports could have been through the SOE only and this fact has also been suppressed by the applicant as they have tried to make out a case that the exports were through their JV partner



YPJCCIF (PP-Unit). In their clarification dated 5<sup>th</sup> May 2005, they have again provided an apparently incorrect statement by clarifying that the exports during the POI was actually done by Mr Zhang Guo Yi & others, which did not appear to have a legal entity within the JV set up. Even if the export was conducted by Mr Zhang Guo Yi and others in their individual capacities, as has been made out, they could not have used the export licence of YPJCCIF which is a SOE. In the same clarification the applicant again submits that Groupstars exported through YPJCCIF during the POI to honour the commitments made by YPJCCIF earlier and they do not wish to export through YPJCCIF in future. This clearly contradicts their statement that the export was done by Mr Zhang Guo Yi and others.

54. It was also noticed that the Mr Zhang Guo Yi is the majority shareholder in the JV out of the 40% portion of the shares held by the erstwhile employees of the PP Unit and is the Director of the JV and at the same time he continues as the legal representative of the YPJCCIF (SOE). The applicant has submitted that there is no legal bar in Chinese law for Mr Zhang Guo Yi to protect his individual interests and he has been retained by the SOE during its process of transition.

55. The above submissions of the applicant and the domestic industry and examination of the issues by the Authority indicates that

- Though 40% of the shares of the JV are held by the erstwhile employees of PP Unit, identity and status of the YPJCCIF (PP) unit, as a separate entity within the JV and its role in the export of the product under consideration as claimed by the applicant is blurred and not supported by any credible evidence.
- The applicant has clearly produces incorrect and inconsistent information as far as the composition of the JV and status of YPJCCIF is concerned. The original YPJCCIF admittedly continues as a state-owned enterprise and was involved in the export of the product during the POI. The documents of transition/transfer of PP unit submitted by the applicant shows that YPJCCIF (SOE) is the JV partner.
- The applicant has further misrepresented the Authority to believe that the exports during the POI, were effected by a private company related to the applicant, which does not appear to be true. The exports are clearly through the SOE. No categorical clarification about the exporter and its status has been given.
- Mr Zhang Gyu Yi, is the common factor in the JV as well as the SOE and due to his involvement in both the entities their relationship has remained all the more confusing. Sometime he has been shown to represent the YPJCCIF (SOE) and sometime he has been shown to represent the so-called YPJCCIF (PP) unit.

56. In view of the foregoing, the Authority finds that the applicant for the review has clearly placed incomplete, inaccurate and inconsistent information before the Authority to hold that the Potassium Permanganate Plant of the erstwhile state-owned enterprise bearing the name M/s Yunnan Province Jiansui Chemical Company Factory was transferred to the Joint Venture company formed in 2001 and the original company with the same name was transferred to private hands with the majority shareholding by Mr Zhang Guo Yi and the employees of the company and with effect from April 2001 both the companies, i.e. Groupstars (Yunnan) LLC China and M/s YPJCCIF, continue to operate as two private companies under the Chinese Joint Venture Law and Chinese Company law respectively. The above

examination also clearly establishes the fact that the applicant for the review has submitted inconsistent, inaccurate and incorrect information and withheld information from the Authority about the status of YPJCCIF as it exists today.

57. In addition to the above it was also noted that the export realization of the YPJCCIF as the exporter of the subject goods manufactured by Groupstar is less than its VAT paid purchase price from Groupstar because of the fact that VAT refund is not available to the exporter in this case. This loss on account of VAT and other SGA expenses have been absorbed by the exporter, which is clearly a state-owned enterprise.

58. The status of the JV also remains unclear in view of the fact that on the one hand the JV documents show YPJCCIF as 40% partner of the JV and on the other hand the share certificates shows that this 40% has been held by the employees of the PP unit.

59. In view of the foregoing the Authority is of the view that the applicant has not provided sufficient evidence to demonstrate that their business decisions are not subject to state interference. Further, on the basis of the examination, the Authority notes that the transactions have not been carried out without significant distortions, which is evidenced by the transactions with the state controlled YPJCCIF. Therefore, the Authority holds that the producer-exporter cannot be extended market economy treatment under the above circumstances. Accordingly, Normal value in respect of this exporter has been worked out based on facts available and non-market economy presumption.

**b) M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China**

60. M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China submitted its response through M/s Kanhaiyalal & Co., Pune. However, the questionnaire response was found incomplete as several appendices to the standard questionnaire were not furnished alongwith the response. The applicant also failed to file a complete and meaningful response to the market economy questionnaire even after issue of a deficiency note to the company in this regard. In view of the above, neither their market economy claim, nor the general questionnaire response data could be accepted by the Authority. Therefore, the above named exporter from China has been treated as non-cooperative for the purpose of this investigation and the data submitted by it has been rejected. Accordingly, all determinations in respect of this exporter have been based on facts available and non-market economy presumption.

**E.3.2 Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin, PR China**

**E.3.2.1 Normal Value: All exporters from China**

61. The Authority notes that the applicant's request for determination of normal value on the basis of their domestic sales transaction and grant of market economy

status of the said purpose has been rejected in view of the reasons recorded in the previous section. The only other exporter who filed a partial response to the mid-term review initiation is M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China. However, the data produced by this exporter was incomplete and the exporter did not adequately rebut the non-market economy presumption. Therefore, this exporter was declared non-cooperative by the Authority. No other exporter from China made any submission. Since none of the responding exporters have met the requirements for grant of individual market economy status for the purpose of determination of individual normal value in terms of Paragraph 8 of Annexure-I of the Antidumping Rules the Authority constructed the normal value for all Chinese exporters in terms of para 7 of the Annexure-I of the Antidumping rules, based on cost of raw materials in the country of exports and cost of utilities and other associated costs as determined by the Authority and a profit margin of \*\*\*% on the cost of production. Constructed normal value for all exporters worked out as US\$\*\*\*\*\* Per MT.

### **E.3.2.2 Export Price: M/s Groupstars LLC China**

62. M/s Group stars and YPJCCIF in their combined submissions have provided information on their exports to India. During the POI Group stars have supplied 11 consignments to YPJCCIF and YPJCCIF have, in turn, exported these 11 consignments of 230 MT to India. In the post disclosure submissions the domestic has argued that the producer i.e. M/s Groupstars (Yunnan) LLC has not exported even a single consignment to India during the POI and therefore, it could not be treated as an exporter at the first place. They have argued that Groupstar's supplies to the trader-exporter M/s YPJCCIF has been treated in their own submissions as domestic sales and therefore, they cannot be assigned a separate dumping margin. There can at best be a single dumping margin for the producer-exporter combination. The Authority has examined this argument and also notes that there has been considerable confusion about the actual identity and status of the exporter in this case. In the instant case the producer has not exported even a single consignment to India during the POI. M/s Groupstars has pleaded that they did not export directly during the POI precisely because they did not have an export license at that time. However, subsequently they have started exporting to India and therefore, they have requested for determination of a separate dumping margin for them. They have pleaded that they cannot be wedded to a particular exporter for ever. As long as the chain of export supply could be established the Authority can always determine the export price at the factory gate of the producer. They have cited earlier precedence of determination of separate dumping margin for the producer. The Authority has examined this issue and is of the opinion that as long as the export price can be traced back to the factory gate of the producer there is no reason why a separate dumping margin for the producer cannot be determined if they wish to export directly. In fact the applicant has made it very clear that they do not wish to continue to export through YPJCCIF any more and no separate dumping margin for YPJCCIF would be required. Therefore, a single dumping margin has been worked out for the applicant based on the export price and constructed normal value for China PR.

63. In its post disclosure submissions the domestic industry has also raised certain substantive issues concerning the adjustments applied to arrive at the net ex-factory export price of the trader. The domestic industry has argued that the S&D expenses of the trader and a reasonable profit margin should be deducted from their export price to arrive at the net export price. In this connection the Authority notes that the exports are through a related party which is also a State Owned Enterprise. Therefore, the arguments of the domestic industry in this respect is valid and a profit margin of \*\*% needs to be deducted from the export price to arrive at the net export price. This profit margin would also reasonably cover the indirect S&D expenses by the trader. During the verification it was noticed that the exporter has not claimed the VAT refund on the export sales transactions to India. Therefore, adjustment towards VAT has not been admitted for the purpose of determination of net-export price.

64. Accordingly, net export price has been determined on the basis of actual CIF export price (Net of VAT) of YPJCCIF after allowing for adjustments towards inland and ocean freight, storage and handling charges, insurance etc. and a reasonable profit margin for the trader as explained above as per exporter's records to bring it to Groupstars ex-factory level.

### E.3.2.2 Export Price: All other exporters from PR China

65. M/s Kanheyala, Pune in its post disclosure submission has pleaded that though M/s Chongqing Jialing Chemicals Ltd. PR China has not fully cooperated in the investigation and therefore, the normal value determined for all non-cooperative exporters may be applicable to this exporter, the transaction-wise data of their exports to India should be accepted for determination of their export price and separate dumping margin for them. The Authority has examined these arguments and is of the view that the exporter concerned has not cooperated with the investigation and their data, including their export details could not be verified. It would therefore, not be possible to accept the export price as claimed by the exporter without verification. Accordingly, net export price for all non-cooperating exporters from China PR has been determined based on the lowest export transaction value from the DSGCIS data, after allowing for adjustments towards transportation, ocean freight commission etc. Net export price works out to US\$\*\*\*\*per MT.

Export Price Calculation						
	Sales	Sales	Before FOB	After FOB	Total	Net Export
	with VAT	Net of VAT	Adjustments	Adjustments	Adjustments	Ex-Factory
Groupstars with YPJCCIF	*****	*****	*****	*****	*****	****
Others	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**E.3.2.3 Dumping Margin:**

66. The normal value constructed has been compared with the net export price determined at the ex-factory level to determine the dumping margin. The dumping margin for the exporters from China works out as follows:

Dumping Margin Calculations					
		Constructed Normal	Net Export	Dumping	Dumping
		Value	Price	Margin	Margin %
Groupstars with YPJCCIF		*****	*****	*****	54.93%
Others		*****	*****	*****	66.95%

67. The Dumping Margins so determined for all exporters from China has been found to be significant and above de-minimis.

**F. INJURY DETERMINATION****F.1 Cumulative Assessment of Injury**

68. The Authority notes that there is no dumped import from Chinese Taipei and Hong Kong during the period for which injury is being examined and dumped imports from China alone is being examined in this review therefore, cumulative assessment of injury is not an issue in this case.

**F.2 Continuation of Injury****F.2.1 Views of the interested parties**

69. The domestic industry argues that it continues to suffer material injury due to continued dumping from China even after imposition of the duties. Though the volume of imports decreased temporarily after imposition of duty, the volume has gone up once again due to intensified dumping.

70. The exporters and other interested parties in their various submissions have claimed that the performance of the domestic industry would clearly reveal that there is no injury to the domestic industry on account of the alleged dumped imports. They have argued that in its submissions Universal has accepted that between 2000-01 and POI its sales volumes have increased by about 33% and their sales value has gone up by 17%. However, decline in their domestic selling price is not due to imports from China but due to its own decision to peg the prices at a particular level as reflected in its own submissions. Their output and capacity utilization and market share has improved during this period indicating no injury. In summary the interested parties have argued that the domestic industry has improved its performance and suffers no injury at the moment and injury, if any, is due to their own inefficiencies and therefore, cannot be attributed to the imports from these sources.

## **F.2 Examination by the Authority**

71. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority.

72. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the authorities are required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

73. For the purpose of injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

74. Since positive dumping margin has been established for the exports from China, entire exports from those countries has been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examination.

### **(A) VOLUME EFFECT: Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

75. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined as follows:

#### **i) Import Volumes and share of subject countries:**

76. The domestic industry had raised the issue of correctness of import data as reported by DGCI&S due to unreasonable variation in the prices and indication of imports from unlikely sources. The Authority has examined the transaction level data of DGCI&S. However, no major aberration in the data was noticed requiring rejection of this data. Therefore, the Authority has accepted the data after pruning the same of few unrelated transactions. The import figures of the product under consideration are as follows:



## Quantity in MT

Total Imports and Share in Total Imports								
	2000-01		2001-02		2002-03		Jan-Dec 2003	
	Qty	Share	Qty	Share	Qty	Share	Qty	Share
China	753.407	92%	85.5	81%	200	59%	336	69%
Others	12.754	2%	20.05	19%	141.868	41%	149.968	31%
Total	766.161		105.55		341.868		485.968	

Source: DGCI&amp;S data

77. The data shows that after imposition of antidumping duty in 2001 imports from China fell substantially from 92% of total imports in 2000-01 to 81% in 2001-02 and 59% in 2002-03. However, the imports have again substantially increased during the POI both in absolute term and in relation to the total imports to 69%.

## ii) Demand, Output and Market shares

## a) Production of the Domestic Industry

## Quantity in MT

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Capacity	2400	2400	2400	2400
Output - Qty	2039	2125	2356	2516
Trend	100.00	104.18	115.53	123.38
Capacity Utilization	85%	89%	98%	105%

78. The production data of the domestic industry reveals that the domestic industry has improved its production compared to the base year though there is no capacity addition during this period. The capacity utilization has also improved and the Company is operating above its installed capacity. However, the production is also to be examined with reference to the demand in the domestic market and the ability of the domestic industry to sell in the domestic market.

## b) Sales of Domestic Industry

## Quantity in MT

Particulars	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Sales (Domestic)	*****	*****	*****	*****
Trend	100.00	108.66	112.90	119.86
Sales - (Exports)	*****	*****	*****	*****
Trend	100.00	117.26	127.71	153.58
Sales - Total	*****	*****	*****	*****
Trend	100.00	112.02	118.68	133.03

79. The data above shows that though the production increased by 23%, the domestic sales has increased by 20% whereas major increase in the sales is in the export segment. The domestic industry has argued that un-remunerative price in the domestic market, due to dumped imports, has forced them to increase the exports.

**c) Demand and Market Share**

Particulars	Quantity in MT			
	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
<b>Domestic Demand</b>	*****	*****	*****	*****
Trend	100	69.46	83.80	95.13
<b>Share in Demand</b>				
Domestic Industry	59.06%	92.39%	79.57%	74.42%
China	37.72%	6.16%	11.95%	17.68%
Chinese Taipei	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%
Hong Kong	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Subject Countries	40.30%	6.16%	11.95%	17.68%
Share of Imports	40.94%	7.61%	20.43%	25.58%

80. Total domestic demand of the product under consideration, after declining from 2000-01 till 2002-03 has increased substantially during the POI. The share of domestic industry in the demand, after increasing after imposition of the duty has shown declining trend, whereas the share of China has increased substantially during the corresponding period.

**(B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

81. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from China has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

82. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry (worked out after normating the costing information of the Domestic Industry) have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

**(i) Price undercutting and underselling effects**

Particulars		Values in Rs/MT			
		2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Cost of Production	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100.00	100.00	100.52	100.75
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100.00	100.00	99.67	98.43
Landed Value (without antidumping duty)	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Price under Cutting	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
% Price undercutting		5-15%	5-15%	5-20%	5-20%
Non Injurious Price	Rs./MT				*****
Price underselling	Rs./MT				*****
Price underselling %	%				5-25%

83. The selling price (net sales realization) of the domestic industry shows significant decline. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from China over the entire



period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCIS data of import prices from the subject country.

84. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

85. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed price of imports from China has been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI and cost of production for the remaining years.

86. The price undercutting and price underselling (without considering the antidumping duty in force) has been found to be substantial.

#### (ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

87. The price suppression effect of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries.

88. The cost of production of the subject goods shows substantial increase after the base year and thereafter shows a moderate increase in the last three years. However, the selling price shows decline during the corresponding period indicating the inability of the domestic industry to raise its prices to recover full cost due to price effects of the dumped imports from China. The interested parties have argued that the duty paid import price from China is much above the selling price of the domestic industry and the domestic industry was free to raise its prices to that level. Their inability to do so indicates that the market cannot accept such a high price. The domestic industry seems to have been forced to benchmark its prices with the CIF import price to retain its market share.

#### F.4 Examination of other Injury Parameters

89. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed here as follows:

##### i) Productivity

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
Productivity	MT/Day	5.83	6.07	6.73	7.19
Trend	Indexed	100.00	104.18	115.53	123.38
Productivity per Day - (Considering 350 days of production in a year)					

90. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of its labour productivity of the output and it has been noticed that the productivity has improved because of marginal increase in output and marginal reduction in the workforce. The industry has attempted an improvement in productivity to cut cost and remain competitive. However, improved productivity has not resulted in commensurate profitability.

## ii) Profits and actual and potential effects on the cash flow

91. Though total revenue and cash flow of the domestic industry from its domestic operations has improved due to increase in domestic sales, the industry continues to suffer loss during the investigation period due to declining per unit realization. The industry has not been able to realize a fair price to recover its cost due to prevailing price level of dumped imports.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
<b>Profits</b>					
Cost of Production	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Selling Price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
Profit/Loss	Rs. MT	*****	(****)	(****)	(****)
Total Profit/Loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	*****	(****)	(****)	(****)

## Indexed

		2000-01	2001-02	2002-03	Jan 03 - Dec - 03
NSR Per MT (DI)		100.00	108.46	109.03	109.28
COP Per MT (DI)		100.00	99.69	99.36	98.13
Profit/ Loss Per MT		100.00	-67.98	-85.45	-114.98
Profit/Loss		100.00	-73.87	-96.47	-137.82

## iii) Employment and wages

92. The employment level has declined marginally. But the expenses on account of salary and wages have increased by about 14%. However, increase in the expenses towards salary and wage is in tandem with the increase in production during the comparable periods.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
<b>Employment</b>					
No. of Employee	Nos.	227	237	232	225
Trend	Indexed	100.00	104.41	102.20	99.12
<b>Wages</b>					
Direct Labour	Rs. Lacs	162.70	171.80	197.79	198.38
Trend	Indexed	100.00	105.59	121.57	121.93

**iv) Return on investment and ability to raise capital**

93. The return on capital employed by the domestic industry shows deterioration compared to the base year and previous years.

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Return on Investments					
Gross Block	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Working Capital	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Capital Employed (total)	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Capital Employed Domestic	Rs. Lacs	*****	*****	*****	*****
Profit / Loss - Domestic Sales	Rs. Lacs	*****	(*****)	(*****)	(*****)
Return on Capital Employed	%	*****	(*****)	(*****)	(*****)
Trend	Indexed	100.00	-66.40	-93.47	-150.28

**v) Investment**

94. There has been no capacity addition or any fresh investment by the applicants during the investigation period.

**vi) Magnitude of Dumping**

95. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined against the country named, for the POI, is substantial, even when the antidumping duty is in force.

**vii) Factors affecting prices**

96. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. There is no viable substitute to this product. M/s Universal Chemicals is the sole producer of the subject good in India and therefore, domestic competition does not affect the prices. Therefore, the dumped import prices appear to affect the prices of the domestic industry.

**viii) Inventories**

Particulars	Unit	2000-01	2001-02	2002-03	Jan - Dec - 03
Inventories - at the end of period	MT	*****	*****	*****	*****
Inventories as % of production	%	*****	*****	*****	*****
Trend	Indexed	100.00	71.81	94.03	24.22

97. The domestic industry has been able to liquidate inventories with the imposition of Anti Dumping Duty. However, the exports of the domestic industry rather than its domestic sales appear to have helped in inventory liquidation.

98. The examination of the above economic parameters indicate that though the domestic industry has improved its performance in several parameters including output and sale volumes, this has not translated into improvement in its profitability and the industry still suffers loss in its domestic operation. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry continues to suffer material injury.

#### **F.5 Other Known factors and Causal Link**

##### **i) Volume and prices of imports from other sources**

99. During the POI, other than China, imports have taken place from USA and Switzerland only. However, total import from these two sources is small compared to imports from China. The Authority notes that dumped imports from China constitute about 70% of total imports and imports from all other sources account for remaining 30%. While imports from USA is almost same price level, the imports from Switzerland is at a higher price level. Therefore, these imports do not appear to have significant effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

100. Therefore, volume and prices of imports from China appear to have more adverse effect on the domestic prices, significantly contributing to the current injury of the domestic industry than the imports from any other sources.

##### **ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

101. Total domestic demand of the product under consideration, after declining from 2000-01 till 2002-03 has increased substantially during the POI. The share of domestic industry in the demand after increasing after imposition of the duty has shown declining trend whereas the share of China has increased substantially during the corresponding period. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

##### **iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

102. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. M/s Universal Chemicals is the sole producer of the subject goods in the country. Major portion of the imports of the subject goods takes place from China. Other exporting countries do not have substantial market share in Indian market to effectively compete with these two market players. Therefore, the current injury to the domestic industry cannot be attributed to trade restrictive practices or competition between foreign and domestic producers.

##### **iv) Development of technology and export performance**

103. Production of Potassium Permanganate is not a highly technology intensive process. The production facility of the foreign producer in China was also verified

and it was seen that the producers apply similar production technology and rather old plant and machinery. Therefore, development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry.

104. The export performance of the domestic industry was found to be better than its domestic performance. They have been able to realize higher price in the export market and their export volume has substantially increased during these years. Therefore, export performance cannot be attributed as a reason of injury suffered by the domestic industry.

#### **v) Productivity of the Domestic Industry**

105. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown substantial improvement. Therefore, productivity is not a factor which can be attributed to the injury of the domestic industry. In fact domestic industry has tried to reduce its losses in its domestic operation through improvement in productivity.

106. The above analysis of injury parameters and examination of non-attribution factors indicate that though there is improvement in several parameters in the performance of the domestic industry they do continue to suffer material injury in terms of drop in profitability, cash loss, and price suppression and depression due to the dumped imports from the subject country.

#### **F.6 Determination of Non-injurious Price of the Domestic Industry**

107. Non-injurious Price for the subject goods has been worked out by the costing division after a detailed analysis and scrutiny of information provided by the domestic industry. Weighted average Non-injurious price for the domestic industry has been determined by the Authority as Rs. \*\*\*\*\* per Kg.

#### **F.7 Magnitude of Injury and injury margin**

108. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the weighted average landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin and the injury margins have been worked out to be positive.

#### **G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

109 The Authority has already established that dumping is continuing from China in spite of the antidumping duty in force and the domestic industry continues to suffer material injury due to such dumped imports. Therefore, examination of the likelihood of recurrence of dumping and injury is not required. However, the Authority has examined the likelihood of continuation of dumping and injury in the event of withdrawal or variation in the duty. The Article 11.2 of the ADA provides that

*The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.*

110. The domestic industry has pleaded that the current state of the condition of the domestic industry is not the material fact for a review of this nature. They plead that in a midterm review the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to arrive at a decision to continue or vary or remove the duty so as to offset dumping. The domestic industry in its submission has quoted the law and practices and standards of reviews in several countries to highlight the fact that determination of likelihood of 'continuation or recurrence of dumping and injury' is vital in a review investigation. They have *inter alia* submitted:

- i. That the Chinese producers in general and the petitioner in particular, are still dumping material in the Indian market.
- ii. That Domestic industry is suffering continued injury due to dumped import from subject countries and should the Anti Dumping Duty be revoked, the injury to the domestic industry would recur or intensify.
- iii. That export price and landed price of imports from China and subject countries has not materially changed over the years. In fact, it may have, at best, further declined in US \$ term after imposition of Anti Dumping Duty;
- iv. That Volume of imports from subject countries first declined due to anti dumping duty in force and thereafter increased. This clearly shows that the Chinese exporters can not sell in the Indian market without resorting to dumping. As regards subsequent increase in the import volumes, domestic industry understands that large scale imports are being made taking undue advantage of duty free import exemptions granted by the Govt. of India;
- v. There is increase in the cost of production. However, the Chinese exporters have reduced their export price to India;

- vi. There is decline in selling price of the domestic industry. The price at which domestic industry is selling material is not a remunerative price.
- vii. That the Chinese producers are holding significant surplus capacities and the demand in China is significantly below the capacities created by them. It has been argued that China's production of over 20,000 Tonnes per year of the subject goods is far in excess of its domestic consumption and therefore, they have to be necessarily exported. Therefore, there is a great possibility that revocation of duty would lead to surge in imports and severe injury to the domestic industry.

111. The Authority has examined all these arguments. It has also been brought to the notice of the Authority that Chinese exports are already attracting antidumping duty in the USA and the EU for past several years and a review is underway in the EC. Therefore, their major markets being already affected because of the antidumping duty in force, Chinese exporters would be looking for alternative markets. Therefore, revocation of duty would most likely lead to continuation of dumping.

112. It has already been established that dumping is continuing in spite of the fact that duty is in force against China, though volume has considerably declined. Considering the extent of dumping margin and the volume of current imports as well as the volume of exports of Chinese exporters to other countries, the Authority holds that dumping will continue to occur if the duties are withdrawn.

113. As far as continuation or recurrence of injury to the domestic industry is concerned the Authority has examined the price levels at which the goods are entering Indian market from the subject country in spite of the duty in force. There is a significant price undercutting and underselling by the Chinese exporters while the landed value of current imports without antidumping duty is compared with the net sales realization and non-injurious price of the domestic industry. There is no indication or valid argument that the price structure of imports from the subject country will change once the duty is revoked. On the contrary looking at the spare capacity and demand supply position in China there is every likelihood that the price level may further depress causing further injury to the domestic industry, if the duty is revoked.

#### **I. Conclusions**

114. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury the authority concludes that:

- i) The subject goods have entered from the Republic of China at less than its fair value and the dumping margins of the subject goods imported from China are substantial and above de minimis level;

- ii) There is also a likelihood of dumping to continue or recur from China if the duties are revoked;
- iii) The domestic industry continues to suffer marginal material injury at present and the cause of the current injury is due to the volume as well as price effect of the dumped imports from the Republic of China;
- iv) Injury to domestic industry is likely to continue if the duties are revoked in respect of imports from Republic of China.
- v) Therefore, continued imposition of the antidumping duty is warranted against goods originating in or exported from China to offset dumping.
- vi) There is no imports and therefore, dumping from Chinese Taipei and Hong Kong, during the injury investigation period. There is also no production of the subject goods in these two countries. Therefore, there is no likelihood of dumping to continue and/or recur from Chinese Taipei, if the duties are revoked. However, re-export or transshipment of goods of Chinese origin, if any will be adequately covered under the duty imposed against China. Therefore, continued imposition of duty against these two countries is not warranted.

**J. Indian industry's interest & other issues**

115. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

**K. Recommendations**

116. Having concluded that there is no likelihood of continuation of dumping and injury on account of imports from Chinese Taipei and Hong Kong, the Authority finds no justification for continuation of the duty against these countries and therefore, recommends revocation of duty in force against these countries.

117. However, in view of positive determination of continuation of dumping, injury and causal links as well as likelihood of continuation of dumping and injury on account of imports from Peoples Republic of China, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from that country. However, considering the current level of dumping from that country and injury suffered by the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, Authority considers it necessary and recommends continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods from Peoples Republic of China in the form and manner described hereunder.



118. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from China PR, equal to lower of margin of dumping and the margin of injury, so as to offset dumping and remove the injury to the domestic industry. The Authority notes that the duty in the original investigation was imposed on fixed price basis. Therefore, the Authority considers it appropriate to impose the antidumping duty on fixed duty basis and accordingly, recommends imposition of definitive antidumping duty as indicated in Col 9 of the table below, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from China.

#### L. Further Procedures

119. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

120. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.

#### Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.	2841.61	Potassium Permanganate KmnO4	All Grades	China	Any	M/s Groupstar Yunnan, LLC, China	Any	285	MT	US\$
2.	2841.61	Potassium Permanganate KmnO4	All Grades	China	Any	Any (other than above)	Any	352	MT	US\$
3.	2841.61	Potassium Permanganate KmnO4	All Grades	Any	China	Any	Any	352	MT	US\$

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority